साान्ध्य हिन्दी दैनिक

जौनपुर से प्रकाशित

देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

वर्ष - 03 | अंक - 44 | जौनपुर, सोमवार, 30 सितम्बर 2024 | सान्ध्य दैनिक (संस्करण) | पेज - 4 | मूल्य - 2 रूपये

संक्षिप्त खबरें

अगर पाकिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध होते तो भारत उसे बड़ा राहत पैकेज देता - राजनाथ

श्रीनगर, एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यदि पड़ोसी देश ने भारत के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखे होते तो भारत पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से मांगे गए पैकेज से भी बड़ा राहत पैकेज देता। बांदीपुरा जिले के गुरेज विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सिंह ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014–15 में जम्मू–कश्मीर के लिए घोषित प्रधानमंत्री विकास पैकेज का जिक्र किया। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा, "मोदी जी ने 2014–15 में जम्मू–कश्मीर के विकास के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की थी जो अब 90,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। यह राशि पाकिस्तान द्वारा आईएमएफ से मांगी गई राशि (राहत पैकेज के रूप में) से कहीं अधिक है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रसिद्ध कथन का उल्लेख किया कि "हम दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते"। उन्होंने कहा, , मेरे पाकिस्तानी दोस्तों, हमारे बीच तनाव पूर्ण संबंध क्यों हैं, हम पड़ोसी हैं।

सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टालरेंस के लिए प्रतिबद्ध - सीएम योगी

गोरखपुर, संवाददाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सुरक्षा के बेहतरीन माहौल में ही निवेश आता है। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो उसकी पूंजी कैसे सुरक्षित रह पाएगी। पर, सुरक्षा के इस शानदार माहौल से, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति से उन लोगों और उनके आकाओं परेशानी होती है, जिनके लिए अपराध ही पेशा था। जो अपराध ा करने को ही बड़प्पन मानते थे। सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जीरो टॉलरेंस के लिए प्रतिबद्ध है क्योंकि इससे ही वर्तमान सुरक्षित रहेगा और बेहतर भविष्य के लिए वर्तमान का सुरक्षित रहना आवश्यक है। सीएम योगी रविवार को गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के समीप बन रहे औद्योगिक गलियारे में गीडा के सेक्टर 27 में बहुराष्ट्रीय कंपनी पेप्सिको की फ्रेंचाइजी मेसर्स वरुण बेवरेजेज के 1170 करोड़ रुपये के निवेश से लगी यूनिट (शीतल पेय बॉटलिंग एवं डेयरी उत्पाद संयंत्र) का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद यहां आयोजित समारोह को संबोधित कर रहे थे। कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं का आह्वान किया है कि वे नौकरी की बजाय उद्यमिता पर अधिक ध्यान दें। रोजगार के लिए और अधिक अवसर पाने के लिए उद्यमिता सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है। आधुनिक विकास की नई ऊंचाइयों को छूने वाले जिन देशों ने उद्यमिता, शोध और नवाचार पर ध्यान दिया है, वही देश आर्थिक परिदृश्य में केंद्र बिंदु में हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं के रोजगार के लिए, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जो अवसर चाहिए उनमें निवेश सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सुखद स्थिति है कि बीते सात साल में उत्तर प्रदेश निवेश का बेहतरीन गंतव्य बन चुका है। यूपी में निवेश के सवाल को लिया चुनौती के रूप में, संकल्प से बनाया बेहतरीन डेस्टिनेशन

सीएम योगी ने कहा कि 2017 में जब पहली बार उनकी सरकार बनी तो उत्तर प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को तलाशने के लिए टीम को लगाया गया। टीम ने रिपोर्ट दी कि प्रदेश में 20 हजार करोड़ रुपये का निवेश आ सकता है। तत्समय 23 करोड़ की आबादी वाले राज्य में मात्र 20 हजार करोड़ के निवेश को लेकर बताया गया कि यूपी में निवेश कौन करेगा। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने इस सवाल को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और संकल्प लिया कि उत्तर प्रदेश को ऐसा बनाएंगे, जहां देश और दुनिया के निवेशक निवेश करने आएंगे। इसके लिए जिस स्पीड में काम किया गया उसका परिणाम रहा कि फरवरी 2023 में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूपी को 40 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले। इनमें से 10 लाख करोड़ के निवेश प्रस्तावों का पीएम मोदी की उपस्थिति में हुए ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में शिलान्यास हो चुका है। जबकि 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतरने के लिए पाइप लाइन में हैं।

तीन–चार साल में ही गीडा में हुआ 12 हजार करोड़ का निवेश

सीएम ने कहा कि गीडा के शिलान्यास के बाद 1998 तक उद्योग लगने का नाम तक नहीं था। धरना प्रदर्शन, लाठी चार्ज, गोली चलने से कोई निवेश के लिए आना नहीं चाहता था। इन समस्याओं का समाधान किया गया, निवेशकों से संवाद बढ़ाया गया। परिणाम है कि बीते तीन–चार सालों में ही गीडा में 12 हजार करोड़ रुपये का निवेश हो चुका है।

सुगमता से बढ़ते कार्यक्रम से आ रहा निवेश, बढ़ रहा रोजगार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि निवेश को धरातल पर उतारने के लिए लैंड बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बेहतरीन होना जरूरी है। सरकार ने इन सब पर पूरा ध्यान दिया। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए डिजिटल प्लेटफार्म तैयार किए। निवेश मित्र पोर्टल जहां 450 से अधिक एनओसी के लिए सिंगल विंडो प्लेटफार्म है तो वहीं निवेश सारथी से निवेश एमओयू की मॉनिटरिंग होती है।

राष्ट्रपति ने हैदराबाद में भारतीय कला महोत्सव का उद्घाटन किया

नई दिल्ली, एजेंसी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को यहां राष्ट्रपति निलयम में भारतीय कला महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया। आठ दिवसीय कला महोत्सव में पूर्वोत्तर राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा की कला, संस्कृति, शिल्प और पाक विवि धता को प्रदर्शित किया जाएगा। मुर्मू ने इस अवसर पर कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों की सांस्कृतिक विविधता, संगीत, कला और पारंपरिक पोशाक देश की विरासत हैं। उन्होंने कहा कि महोत्सव देशवासियों को क्षेत्र की परंपराओं और समुदायों से परिचित कराने का एक प्रयास है। मुर्मू ने विश्वास जाहिर किया कि यह सांस्कृतिक कार्यक्रम देश के पूर्वोत्तर और दक्षिण राज्यों के बीच सेतु का काम करेगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले आठ दिनों में कई लोग महोत्सव में आएंगे और पूर्वोत्तर की संस्कृति से जुड़ेंगे। यह आयोजन सांस्कृतिक आदान–प्रदान को बढ़ावा देने का भी एक अवसर है। मुर्मू ने कहा कि पूर्वोत्तर के लोग अपने आतिथ्य, कड़ी मेहनत और उत्साह के लिए जाने जाते हैं तथा जब भी वह वहां जाती हैं तो उन्हें लोगों का प्यार मिलता रहा है। देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और उसका संवर्धन करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों और अन्य लोगों की सराहना की तथा कार्यक्रम के आयोजन के लिए केंद्रीय संस्कृति और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय की भी सराहना की। इससे पहले राष्ट्रपति ने यहां नालसार विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी भाग लिया।

दुनिया में विनिर्माण का 'पावरहाउस' बना भारत - पीएम मोदी

नयी दिल्ली, एजेंसी। पीएम नरेन्द्र मोदी ने रविवार को कहा कि भारत आज दुनिया में विनिर्माण का 'पावरहाउस' बन गया है और सभी देशों की नजरें ''हम पर टिकी हैं'' क्योंकि सरकार वैश्विक गुणवत्ता वाली चीजों के निर्माण के साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। आकाशवाणी के मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 114वीं कड़ी में मोदी ने देशवासियों से त्योहारों के मौसम में उपहार स्वरूप 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को एक–दूसरे को देने का आह्वान किया। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम के 10 वर्ष पूरे होने का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि इस अभियान की सफलता में, देश के बड़े उद्योगों से लेकर छोटे दुकानदारों तक का योगदान शामिल है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह देखकर बहुत खुशी मिलती है कि गरीब, मध्यम वर्ग और सूक्ष्म व मध्यम उद्योग को इस अभियान से बहुत फायदा मिल रहा है और इस अभियान ने हर वर्ग के लोगों को अपनी प्रतिभा सामने लाने का अवसर दिया है। मोदी ने कहा, ''आज, भारत विनिर्माण का पावरहाउस बन गया है और देश की युवा–शक्ति की वजह से दुनिया–भर की नजरें हम पर हैं। ऑटोमोबाइल्स हो, टेक्सटाइल्स हो या फिर उड्डयन का क्षेत्र या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा का क्षेत्र हो। हर क्षेत्र में देश का निर्यात लगातार बढ़ रहा है।'' प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) का लगातार बढ़ना भी 'मेक इन इंडिया' की सफलता की गाथा कह रहा है। उन्होंने कहा कि देश अब वैश्विक गुणवत्ता वाली चीजों के निर्माण के साथ ही स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। महाराष्ट्र के भंडारा जिले में 50 से भी अधिक स्वसहायता समूहों की ओर से टसर सिल्क को संरक्षित करने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह स्थानीय समुदायों को सशक्त बना रही है और साथ ही 'मेक इन इंडिया' की भावना को भी दर्शा रही है। उन्होंने त्योहारों के इस मौसम में 'मेड इन इंडिया' उत्पाद को बढ़ावा देने का आह्वान करते हुए कहा, ''आप कुछ भी उपहार देंगे, वह 'मेड इन इंडिया' ही होना चाहिए।'' मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि सिर्फ मिट्टी के दीये खरीदना ही 'वोकल फॉर लोकल' नहीं है बल्कि इसके साथ ही अपने क्षेत्र के स्थानीय उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाना जरूरी है।

महबूबा मुफ्ती हमेशा से पाकिस्तान की भाषा बोलती रही - गिरिराज सिंह

पटना, एजेंसी। केंद्रीय कपड़ा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता गिरिराज सिंह ने पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को पाकिस्तान परस्त बताया है। आरोप लगाया है कि महबूबा कभी अमन चौन का पैगमा नहीं देती हैं। गिरिराज सिंह ने कहा, हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत से दुख है तो वह फारूख अब्दुल्ला से जाकर मिलें। गले मिलकर दुख प्रकट करें। महबूबा मुफ्ती तो शुरू से ही पाकिस्तान की भाषा बोलती रही हैं। उन्होंने अपनी भाषा के माध्यम से कभी अमन, शांति का पैगाम तो दिया नहीं है। दरअसल, इजरायली हमले में मारे गए हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के समर्थन में महबूबा मुफ्ती ने एक पोस्ट किया था। उन्होंने लिखा, ''लेबनान और गाजा के शहीदों, खास तौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता दिखाने के लिए मैं कल अपना अभियान रद्द कर रही हूं। हम इस दुख की घड़ी में फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं।'' पीडीपी प्रमुख के इस पोस्ट के बाद से भाजपा के तमाम नेता लगातार महबूबा मुफ्ती पर प्रहार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता ने भी महबूबा मुफ्ती की मंशा पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, महबूबा मुफ्ती जो हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर आंसू बहा रही हैं, इनके आंसू तब नहीं बहते हैं जब बांग्लादेश में हिन्दुओं को मौत के घाट उतारा जाता है। इजरायली हमले में हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह मारा गया था।

कांग्रेस और भाजपा को अपना वोट देकर इसे खराब न करें - मायावती

लखनऊ, संवाददाता। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की अध्यक्ष मायावती ने कांग्रेस पर दलितों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए रविवार को कहा कि दलित समाज के लोग कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपना वोट देकर इसे खराब न करें। बसपा प्रमुख ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दलितों से यह अपील की। बसपा प्रमुख ने अपने आधिकारिक 'एक्स' खाते पर शृंखलाबद्ध पोस्ट में कहा, ''हरियाणा में विधानसभा चुनाव के वक्त भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा व तिरस्कार से यह साबित है कि पार्टी में जब अभी सब ठीक नहीं है तो आगे क्या होगा? ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस व भाजपा आदि को वोट देकर इसे खराब न करें...।'' उन्होंने कहा, ''वैसे भी हमेशा आरक्षण विरोधी रही कांग्रेस के नेता अब आरक्षण को समय आने पर खत्म करने की बात करते हैं।

हरियाणा में हो रहे विधानसभा आमचुनाव के दौरान भी कांग्रेस द्वारा दलितों की लगातार की जा रही उपेक्षा व तिरस्कार से यह साबित है कि पार्टी में जब अभी सब कुछ ठीक नहीं है, गलत है तो आगे क्या होगा? ऐसे में दलित समाज के लोग कांग्रेस व बीजेपी आदि को अपना वोट देकर इसे खराब न करें। मायावती ने कहा, ''अतः दलित अपना वोट बसपा को ही दें क्योंकि यही पार्टी उनके हित व कल्याण की सुरक्षा तथा संवैधानिक हक दिलाकर उन्हें शासक वर्ग बनाने के लिए लगातार संघर्षरत है।'' बसपा प्रमुख ने कहा, ''साथ ही जम्मू–कश्मीर में दलित वर्ग के लोगों कोकांग्रेस, भाजपा व अन्य किसी भी गठबंधन के मिथ्या वादे व अन्य बहकावे आदि में नहीं आना है। इनके दलित विरोधी इतिहास को ध्यान में रखते हुए अपना कीमती वोट बसपा को ही दें।'' 2. वैसे भी हमेशा आरक्षण विरोधी रही कांग्रेस के नेता अब आरक्षण को समय आने पर खत्म करने की बात करते हैं। अतः दलित अपना वोट एकतरफा तौर पर बीएसपी को ही दे।

लाडकी बहिन योजना को बंद करने की ताकत किसी में नहीं - शिंदे

मुंबई, एजेंसी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार को कहा कि सरकार की प्रमुख योजना 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिन योजना' को बंद करने की ताकत किसी में नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार फिर से सत्ता में आती है तो 1,500 रुपये की मासिक राशि बढ़ा दी जाएगी। यहां 'हिंदू हृदय सम्राट बालासाहेब ठाकरे स्मृति उद्यान' के उद्घाटन कार्यक्रम में शिंदे ने महिला लाभार्थियों से उन 'सौतेले भाइयों' (विपक्ष के संदर्भ में) से सावधान रहने को कहा, जो योजना को बंद करने के लिए बाधा डाल रहे हैं। उन्होंने कहा, ''योजना जारी रहेगी। लाडकी बहिन योजना को रोकने की ताकत किसी में नहीं है। मैंने अपनी बहनों से कहा है। 'सौतेले भाइयों' से सावधान रहें, क्योंकि वे पहले दिन से ही बाधा डाल रहे हैं।

उन्होंने योजना को रोकने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया। यह भाई केवल 1,500 रुपये पर नहीं रुकेगा। हम धनराशि बढ़ाएंगे।'' उन्होंने कहा कि वह सभी 'प्यारी बहनों' को लखपति बनाना चाहते हैं।

शिवसेना और अपने पूर्ववर्ती उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष करते हुए शिंदे ने कहा कि विपक्ष दावा करता है कि 'लाडकी बहिन' योजना के तहत दी गई 1,500 रुपये की राशि कम है, लेकिन जब वे सत्ता में थे तो उन्होंने यह राशि भी नहीं दी।

पीएलआई स्कीम में निवेश से देश में 40 प्रतिशत बढ़ेंगे रोजगार के अवसर - गोयल

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम के तहत निवेश आने के कारण रोजगार के अवसर 40 प्रतिशत बढ़कर 12 लाख पर पहुंच जाएंगे,

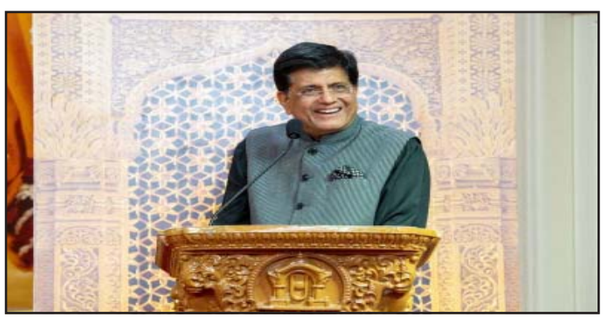

जो कि फिलहाल 8.50 लाख पर हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की ओर से पीएलआई योजनाओं के सीईओ से बातचीत करते हुए रविवार को यह बयान दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएलआई स्कीम और श्मेक इन इंडियाश दोनों एक–दूसरे के पूरक बन गए हैं। आज के समय में दोनों को अलग करके देखना कठिन है। पीएलआई स्कीम के तहत उत्पादन बढ़कर आने वाले समय में 11 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच सकता है, जो कि मौजूदा समय में 9 लाख करोड़ रुपये पर है। गोयल ने आगे कहा कि सरकारी खरीद में हमें सेक्टर के हिसाब से कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है, जहां घरेलू मूल्यवर्धन कम है। मैंने अपने अधिकारियों से इसे लेकर रोडमैप पर चर्चा की है कि वे कैसे क्लास–1 और क्लास–2 आपूर्तिकर्ता बन सकते हैं। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के मुताबिक, क्लास–1 आपूर्तिकर्ता वे होते हैं, जिनके उत्पादों में स्थानीय कंटेट 50 प्रतिशत या उससे अधिक होता है। वहीं, क्लास–2 आपूर्तिकर्ता वे होते हैं, जिनके उत्पादों में स्थानीय कंटेंट 20 प्रतिशत से अधिक, लेकिन 50 प्रतिशत से कम होता है। गोयल ने आगे कहा।

उत्तर बंगाल में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक - सीएम ममता

कोलकाता, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उत्तरी जिलों में बाढ़ की स्थिति को ''खतरनाक'' बताया और दावा किया कि राज्य को इस प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए केंद्र सरकार से सहायता नहीं मिल रही है। बंगाल के उत्तरी हिस्से में बाढ़ की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वहां जा रहीं बनर्जी ने संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार युद्ध स्तर पर बाढ़ से निपट रही है। मुख्यमंत्री ने सिलीगुड़ी जाते समय कहा, ''उत्तर बंगाल बाढ़ की चपेट में है। कूचबिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार जैसे जिले प्रभावित हुए हैं।

कोशी नदी के जलग्रहण क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण, बिहार के कई स्थान और बंगाल के मालदा और दक्षिण दिनाजपुर जिले निकट भविष्य में प्रभावित होंगे। केंद्र सरकार पर ''राज्य को आपदाओं से लड़ने में मदद करने के लिए अपनी भूमिका नहीं निभाने'' का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा, ''हमारे बार–बार याद दिलाने के बावजूद केंद्र ने फरक्का बैराज का रखरखाव कार्य नहीं किया और इसकी जल–धारण क्षमता काफी हद तक कम हो गई है।

क्षतिग्रस्त पीडब्ल्यूडी सड़कों की मरम्मत होगी, दिल्ली बनेगी गड्ढा मुक्त - सीएम आतिशी

नयी दिल्ली, एजेंसी। मुख्यमंत्री आतिशी ने रविवार को कहा कि अक्टूबर के अंत तक लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की सभी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हो जाने के बाद दिल्ली गड्ढों से मुक्त हो जाएगी। आतिशी ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि वह और दिल्ली सरकार के सभी मंत्री सोमवार से शहर भर की सड़कों का स्थलीय निरीक्षण शुरू करेंगे ताकि नुकसान की सीमा और आवश्यक मरम्मत का आकलन किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में पीडब्ल्यूडी की 1,400 किलोमीटर लंबी सड़कों की व्यापक समीक्षा उनकी अध्यक्षता में हुई बैठक में की गई जिसमें सभी मंत्री और पीडब्ल्यूडी अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि सोमवार से सभी मंत्री एक सप्ताह तक अपने–अपने क्षेत्रों में सड़कों का निरीक्षण करेंगे और मरम्मत की जरूरत का पता लगाएंगे। मुख्यमंत्री

दक्षिण और दक्षिण–पूर्वी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी सड़कों का निरीक्षण करेंगी, मंत्री सौरभ भारद्वाज पूर्वी दिल्ली में, गोपाल राय उत्तर–पूर्वी दिल्ली में, कैलाश गहलोत पश्चिम और दक्षिण–पश्चिमी दिल्ली में, इमरान हुसैन नयी दिल्ली और मध्य दिल्ली में तथा मुकेश अहलावत उत्तर और उत्तर–पश्चिमी दिल्ली में पीडब्ल्यूडी सड़कों का निरीक्षण करेंगे।

संपादकीय

अपनो से लड़ती भाजपा

चुनावी राज्य हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने उनके काम को मुश्किल बना दिया है। उनका दावा है कि भाजपा के खिलाफ मतदाताओं में गुस्सा मुख्य रूप से खट्टर के बारे में लोगों की धारणा के इर्द–गिर्द है, जिन्होंने नौ साल से अधिक समय तक राज्य पर शासन किया। एक भाजपा कार्यकर्ता ने कहा, मतदाता खट्टर को एक अक्षम और अहंकारी मुख्यमंत्री के रूप में याद करते हैं। इस असंतोष का मुकाबला करने के लिए, भगवा पार्टी ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले खट्टर की जगह अपेक्षाकृत युवा और विनम्र नायब सिंह सैनी को लाया था। हालांकि, खट्टर के खिलाफ गुस्सा तब से बना हुआ है, जब बाद में उन्हें नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण पद दिया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं का मानना घ्है कि खट्टर की लगातार सफलता का कारण यह है कि वे ष्मोदीजी के दोस्तष हैं। मोदी ने एक बार खट्टर द्वारा उन्हें अपनी बाइक पर घुमाने की यादों को ताजा किया था। खट्टर ने उम्मीदवारों के चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और चुनाव प्रचार कर रहे थे। हालांकि, उनके अभियान मतदाताओं को और अधिक नाराज कर रहे हैं। हाल ही में एक पार्टी मीटिंग में, एक कार्यकर्ता ने घोषणा की कि हिसार के उम्मीदवार का हारना तय है। इसके बाद खट्टर ने अपने सुरक्षाकर्मियों को आदेश दिया कि वे कैडर को कमरे से बाहर निकाल दें। घटना का वीडियो मीडिया में चर्चा का विषय बन गया, जिससे पार्टी के प्रबंधकों में चिंता की लहर दौड़ गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहरसा में मत्स्य विभाग की एक प्रदर्शनी देखने गए थे। प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे और आयोजक खुश थे। लेकिन जैसे ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, दर्शकों में से कई लोगों ने स्टॉल पर धावा बोलना शुरू कर दिया और मछलियाँ चुराने के लिए छोटे–छोटे पोर्टेबल टैंकों में कूद पड़े। ऐसी स्थिति में उन्हें प्रदर्शित करने वाली सरकारी और निजी एजेंसियाँ असहाय थीं। भारी पुलिस बल की मौजूदगी भी लूट को रोकने में विफल रही। इस हाथापाई में एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना गया कि वह मुख्यमंत्री को सुनने नहीं आया था, बल्कि घर पर पार्टी करने के लिए मछली ले जाने आया था। कुछ ही मिनटों में मछलियाँ गायब हो गईं, जिससे भाग लेने वाले उद्यमियों के मुँह में बुरा स्वाद रह गया, जिन्हें हजारों रुपये का नुकसान हुआ। यह घटना दर्शाती है कि लोगों में कानून और सरकार के प्रति एक तरह की अवहेलना घर कर गई है। सीता की गिनती नीतीश कुमार ने सहरसा में मछली की लूट की दुस्साहसिक घटना की उम्मीद नहीं की होगी, लेकिन सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम तक बेहतर रेल और सड़क संपर्क की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की गई उनकी अपील को बिहार के लोगों ने खूब सराहा। सीतामढ़ी को देवी सीता की जन्मस्थली माना जाता है और राज्य के लोगों को नई दिल्ली से त्वरित प्रतिक्रिया की उम्मीद थी। हालांकि, केंद्र की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बारे में पूछे जाने पर भाजपा नेताओं ने बताया कि मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका की अपनी यात्रा में व्यस्त हैं। यह कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) के नेताओं को पसंद नहीं आया। उनमें से एक ने पलटवार करते हुए कहारू "या तो प्रधानमंत्री देवी सीता के लिए बहुत व्यस्त हैं या उन्हें अनदेखा कर रहे हैं... यह अच्छा नहीं है। बिहार के लोग देवी सीता को लेकर बहुत भावुक हैं।" हालांकि, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने सुझाव दिया कि लोगों को इंतजार करना चाहिए क्योंकि यह मांग कुमार की सूक्ष्म राजनीति का हिस्सा है और उचित समय पर उचित जवाब मिलेगा। शक्तिशाली शक्ति भले ही नवीन पटनायक ओडिशा में सत्ता से बाहर हों, लेकिन उन्हें पता है कि राज्य में काम कैसे करवाया जाता है। भुवनेश्वर के भरतपुर पुलिस स्टेशन में सेना के एक कैप्टन और उनकी मंगेतर के साथ कथित दुर्व्यवहार के बाद, मोहन चरण माझी के नेतृत्व वाली सरकार भारी दबाव में आ गई और मामले की आपराधिक जांच के आदेश दिए। कुछ दिनों के बाद, इसने अपनी सतर्कता कम कर दी, यह उम्मीद करते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला आखिरकार शांत हो जाएगा। हालांकि, पटनायक ने इस मुद्दे पर जनता की भावना को सही ढंग से समझते हुए न्यायिक जांच की मांग की। बाद में, उनकी पार्टी, बीजू जनता दल ने शहर में छह घंटे के बंद का आह्वान किया। परेशान होकर, माझी, जो कि केंदुझर के दौरे पर थे, भुवनेश्वर पहुंचे और सभी वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। उसी रात न्यायिक जांच की घोषणा की गई। इसके बाद बीजद ने अपना प्रस्तावित आंदोलन वापस ले लिया। ऐसा लगता है कि पटनायक की जीत हुई। कठोर सबक अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय द्वारा शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को उनकी गौ ध्वज स्थापना भारत यात्रा के लिए अनुमति न देना – जिसका उद्देश्य गाय को माता का दर्जा देना और गोहत्या को रोकने के लिए कानून बनाने का आह्वान करना था – निश्चित रूप से इस संत के लिए एक बड़ा झटका रहा होगा। अरुणाचल प्रदेश में मित्रवत भाजपा और उसके सहयोगी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी (नागालैंड) और नेशनल पीपुल्स पार्टी (मेघालय) के नेतृत्व वाले राज्य प्रशासन ने कोई मदद नहीं की। पूर्वोत्तर अपनी सांस्कृतिक आदतों की कसम खाता है और नहीं चाहता कि कोई भी उनकी आहार संबंधी प्राथमिकताओं को तय करे।

एमएसएमई और उभरते उद्योगों पर देना होगा ध्यान

डॉ. ब्रजेश

मेक इन इंडिया मोदी सरकार की एक प्रमुख योजना है। 25 सितंबर, 2014 को शुरू हुई यह योजना दस वर्ष पूरे कर चुकी है। इस अभियान के कुछ घोषित लक्ष्य थे, जैसे विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 12–14 प्रतिशत प्रति वर्ष करते हुए 2022 तक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में विनिर्माण के योगदान को 25 प्रतिशत तक बढ़ाना और 2022 तक अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र की 10 करोड़ अतिरिक्त नौकरियां पैदा करना। अब इन लक्ष्यों को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। हालांकि मौजूदा गति और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य 2030 तक भी पूरा होता नहीं दिख रहा है। कोविड महामारी के दौरान यह प्रचारित किया गया कि चीन छोड़ने वाली कंपनियां भारत में आएंगी, लेकिन इनमें से अधिकांश ने वियतनाम, ताइवान एवं थाइलैंड की राह पकड़ी और केवल कुछ ही भारत आईं। यह सच है कि सरकार निरंतर आर्थिक विकास करने और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए एक प्रतिस्पर्धी और गतिशील वातावरण बनाने का प्रयास कर रही है और इसके अच्छे परिणाम भी कुछ क्षेत्रों में दिख रहे हैं। भारतीय कंपनियों द्वारा कोविड टीकों का विकास एक बड़ा उदाहरण है। सरकार के प्रयासों के कारण 2014–2023 के दौरान विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। परंपरागत रूप से खिलौनों का आयातक रहा भारत अब निर्यातक बन गया है। अप्रैल–अगस्त 2022 में भारत के खिलौना निर्यात में 2013 की समान अवधि की तुलना में 636 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी तरह मोबाइल उत्पादन 2014–15 में 18,900 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 4,10,000 करोड़ रुपये के अनुमानित बाजार तक पहुंच गया। एयरोस्पेस, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अन्य क्षेत्रों में भी प्रगति हो रही है। आइबीईएफ की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विनिर्माण क्षेत्र ने अब तक का सबसे अधिक निर्यात किया, जो 447.46 अरब डालर तक पहुंच गया है। विश्व बैंक द्वारा जारी ईज आफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2014 में भारत की रैंक 134वीं थी, जो 2023 में बढ़कर 63 हो गई। वैश्विक प्रतिस्पध र्ात्मकता रिपोर्ट इंडेक्स में भारत 43वें स्थान पर है, जो 2014 में 60वें स्थान पर था। इसके बावजूद मैन्यूफैक्चरिंग में संभावनाएं पूरी तरह साकार नहीं हो पा रहीं। इसे अनदेखा नहीं किया जा सकता कि हाल के वर्षों में जनरल मोटर्स, मैन ट्रक्स, यूनाइटेड मोटर्स, फिएट और हार्ले डेविडसन ने भारतीय बाजार से निकलने का फैसला किया। फेडरेशन आफ आटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के अनुसार इन निकासियों के चलते 65,000 नौकरियां चली गईं। एक कंपनी के बंद होने से हजारों श्रमिकों का विस्थापन होता है। हम चीन से तुलना करना पसंद करते हैं। उसकी जीडीपी में मैन्यूफैक्चरिंग की हिस्सेदारी 34 प्रतिशत है। भारत की तुलना में जीडीपी में विनिर्माण का बड़ा हिस्सा रखने वाले अन्य एशियाई देशों में दक्षिण कोरिया (26 प्रतिशत), जापान (21 प्रतिशत), थाइलैंड (27 प्रतिशत), सिंगापुर और मलेशिया (21 प्रतिशत), इंडोनेशिया और फिलीपींस (19 प्रतिशत) शामिल हैं। चीन ने खुद को दुनिया के कारखाने के रूप में स्थापित किया है और वैश्विक विनिर्माण में उसका हिस्सा 22.4 प्रतिशत है, जबकि पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भारत वैश्विक विनिर्माण में बमुश्किल 2.9 प्रतिशत योगदान देता है। चीन से आयात छोटे उद्यमों को बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, क्योंकि सस्ते चीनी सामान के कारण घरेलू कंपनियों

के लिए बाजार में प्रतिस्पर्धा कठिन हो रही है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के अनुसार कई आयातित उत्पाद स्थानीय एमएसएमई द्वारा बनाए जाते हैं और कम लागत वाले चीनी उत्पादों तक आसान पहुंच के कारण उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए चीन भारत के 96 प्रतिशत छाते, 92 प्रतिशत कृत्रिम फूल और मानव बालों से बनी वस्तुओं की आपूर्ति करता है। चीनी आयात ने कांच के सामान में 60, सिरेमिक उत्पादों में 51.4 और संगीत वाद्ययंत्रों में 52, फर्नीचर, बिस्तर और लैंप में 48.7 प्रतिशत, औजार और कटलरी में 39.4 प्रतिशत, पत्थर, प्लास्टर और सीमेंट में 49.3 प्रतिशत, चमड़े की वस्तुओं के बाजार के 54 प्रतिशत तक पर कब्जा कर लिया है। सरकार द्वारा खिलौनों पर सीमा शुल्क 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत करने के बावजूद भारतीय खिलौना बाजार में चीन का 35 प्रतिशत हिस्सा है। इस स्थिति के बारे में विचार किया जाना चाहिए। हाल में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन अभी वांछित नतीजे नहीं मिल सके हैं। पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप की संख्या 350 से 1.48 लाख हो गई, पर आज भी 80 प्रतिशत स्टार्टअप फेल हो रहे हैं। हमें शिक्षा, प्रशिक्षण और आजीवन सीखने के कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यबल के कौशल और क्षमताओं को बढ़ाना होगा, जो उद्योगों की जरूरतों और मांगों से मेल खा सके। समय के साथ स्मार्ट विनिर्माण को बढ़ावा देना होगा और एआइ, रोबोटिक्स आदि जैसी उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना होगा। भारत में एमएसएमई क्षेत्र का विनिर्माण उत्पादन में 45 प्रतिशत से अधिक योगदान है। वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एमएसएमई को अधिक कनेक्टिविटी की आवश्यकता है।

निर्यात बढ़ाने के लिए पीएलआई योजना को एमएसएमई और उभरते उद्योगों तक बढ़ाया जाना चाहिए। भारत भविष्य में खुद को अगला वैश्विक कारखाना बना सकता है, बशर्ते बोझिल नियमों से विनिर्माण क्षेत्र को मुक्त किया जाए। सरकार को यह समझने की जरूरत है कि संसद के माध्यम से कोई विधेयक पारित करना, निवेशक सम्मेलन आयोजित करना आदि औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए पर्याप्त नहीं।

शहबाज शरीफ ने यूएन में कश्मीर पर रोना रोया

विनोद

प्रधानमंत्री मोदी ने न केवल यह याद दिलाया कि किस तरह आठ वर्ष पहले सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था बल्कि यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि नया भारत घर में घुसकर मारता है और गोली का जवाब गोले से देता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से कश्मीर पर जो रोना रोया और भारत पर जैसे मनगढ़ंत आरोप लगाए, भारतीय प्रतिनिधि ने उनका करारा जवाब देकर बिल्कुल सही किया। पाकिस्तान को हर समय यह पता चलना ही चाहिए कि कोई भी उसका रुदन सुनने के लिए तैयार नहीं है और वह अभी भी आतंकवाद को अपना सहयोग, समर्थन और संरक्षण देने से बाज नहीं आ रहा है। यह अच्छा हुआ कि भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाने के साथ ही यह भी बता दिया कि उसे आतंकवाद को संरक्षण देने के दुष्परिणाम भुगतने होंगे– ठीक वैसे ही जैसे उसने भारत की ओर से की गई सर्जिकल स्ट्राइक और फिर एयर स्ट्राइक के रूप में भोगे थे।

इस सिलसिले में जम्मू में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रध ाानमंत्री मोदी ने न केवल यह याद दिलाया कि किस तरह आठ वर्ष पहले सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था, बल्कि यह कहने में भी संकोच नहीं किया कि नया भारत घर में घुसकर मारता है और गोली का जवाब गोले से देता है। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि कांग्रेस के शासनकाल में किस तरह पाकिस्तान की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया जाता था। निःसंदेह यह कांग्रेस को अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच तो यही है कि उसके सत्ता में रहने के दौरान पाकिस्तान को कोई सबक नहीं सिखाया गया। इसके चलते ही उसका दुस्साहस बढ़ा और भारत को इसकी अच्छी–खासी कीमत चुकानी पड़ी। यदि मोदी सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कठोर रवैये का परिचय नहीं देती तो आज सीमा पर जो शांति है, वह नहीं होती और जम्मू कश्मीर में इतने उत्साह भरे माहौल में चुनाव नहीं हो रहे होते। जम्मू कश्मीर में जो शांति का वातावरण बना है, उसका संज्ञान कश्मीर घाटी की जनता को विशेष रूप से लेना चाहिए। उसे इस नतीजे पर पहुंच जाना चाहिए कि पाकिस्तान उसका हितैषी नहीं और वह अभी भी कश्मीर को अशांत–स्थिर करने से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान के इस रवैये पर भारत सरकार को भी ध यान देना होगा, क्योंकि वह आर्थिक रूप से बदहाल हो जाने के बाद भी भारत विरोधी गतिविधियां बंद करने के लिए तैयार नहीं है। इसका प्रमाण इससे मिलता है कि गत दिवस कुलगाम में एक मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराया गया। यह ठीक नहीं कि जम्मू कश्मीर में आतंकी रह–रहकर अपना सिर उठाते रहें। पिछले कुछ समय से तो कश्मीर से अधिक जम्मू में आतंकियों की सक्रियता बढ़ गई है। इसे देखते हुए सरकार को आतंकियों के दुस्साहस का दमन करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने होंगे। इस क्रम में पाकिस्तान को केवल चेतावनी देना ही पर्याप्त नहीं। उसे सही रास्ते पर लाने के लिए उस पर दबाव भी बनाना होगा। उसे इस दबाव का आभास भी कराया जाना चाहिए। यह समझा जाना चाहिए कि वह आसानी से सुधरने वाला नहीं है।

संविधान की आत्मा को जीवित रखने की आवश्यकता

ललित

कभी–कभी मुझे लगता है कि यह हमारे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में सच है। हम लगातार इसकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इसके व्यवहार में इसके अपने सिद्धांतों को भूल जाते हैं। इसका एक उदाहरण, अन्य उदाहरणों के अलावा, विपक्षी शासित राज्यों में राज्यपालों द्वारा निभाई जाने वाली पक्षपातपूर्ण भूमिका है। यह दुरुपयोग किसी एक पार्टी का एकाधिकार नहीं रहा है। कांग्रेस सरकारों ने इसे खुलेआम किया, और 2014 के बाद भाजपा भी इससे अलग नहीं है। यह दुखद है, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि जैसे–जैसे लोकतंत्र विकसित होगा, इसकी कई विकृतियाँ ठीक हो जाएँगी, और आगे नहीं बढ़ेंगी।

राज्यपालों की शक्तियाँ और भूमिका संविधान के अनुच्छेद 152 से 160 के तहत परिभाषित की गई हैं। ये स्पष्ट रूप से बताते हैं कि राज्यपाल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, और इस प्रकार वह दलगत राजनीति से ऊपर होगा, और ष्संविधान और कानून को संरक्षित, सुरक्षित और बचावष करने के लिए काम करेगा। हालांकि, चूंकि राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं, इसलिए कई राज्यपाल, केंद्र में सत्तारूढ़ दल द्वारा नियुक्त किए जाने के कारण, एक गैर–राजनीतिक प्रमुख के बजाय उसके एजेंट के रूप में अधिक व्यवहार करते हैं। राज्यपालों द्वारा अपनी शक्तियों के दुरुपयोग का एक परेशान करने वाला उदाहरण राज्य विधानसभाओं द्वारा विधिवत पारित विधेयकों को मंजूरी देने में देरी करना है। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, पंजाब, कर्नाटक और दिल्ली जैसे विपक्षी शासित राज्यों में इसने गंभीर रूप धारण कर लिया है। कांग्रेस शासित कर्नाटक में, राज्यपाल थावर चंद गहलोत, जो अपनी नियुक्ति तक भाजपा–आरएसएस के वफादार सदस्य थे, ने राज्य विधानमंडल द्वारा पारित 11 विधेयकों को स्पष्टीकरण मांगते हुए वापस कर दिया है। डीएमके शासित तमिलनाडु में, भाजपा द्वारा नियुक्त राज्यपाल आर.एन. रवि ने 31 अक्टूबर, 2023 और 28 अप्रैल, 2024 के बीच की अवधि के दौरान राज्य विधानमंडल द्वारा विधिवत पारित 12 विधेयकों को मंजूरी नहीं दी है। केरल में, भाजपा द्वारा नियुक्त विद्वान आरिफ मोहम्मद खान ने सात विधेयकों को दो साल तक मंजूरी नहीं दी और बाद में उन्हें राष्ट्रपति के पास भेज दिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का दावा है कि राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस, जो पहले भाजपा के सदस्य थे, ने आठ विधेयकों पर अपनी सहमति नहीं दी है। आप शासित पंजाब में, जहां पूर्व में भाजपा के वफादार बनवारी लाल पुरोहित राज्यपाल हैं, चार विधेयक रोक दिए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार विधेयकों को राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त करनी होती है। राज्यपाल संशोधन या पुनर्विचार का सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा षजितनी जल्दी हो सकेष करना चाहिए। हालांकि, अगर राज्य विधानमंडल राज्यपाल के सुझावों को ध्यान में रखते हुए या यहां तक घ्कि अपने मूल रूप में भी विधेयक को फिर से पारित करता है, तो राज्यपाल ष्उस पर अपनी सहमति नहीं रोकेंगेष। राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रख सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब प्रस्तावित कानून उच्च न्यायालय की शक्तियों से वंचित करेगा। नवंबर 2023 में, यह मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आया। तमिलनाडु और केरल के मामले में, शीर्ष अदालत ने तीखे शब्दों में पूछा कि राज्यपाल दो से तीन साल तक विधेयकों पर बैठे रहकर क्या कर रहे हैं। "गंभीर चिंता" व्यक्त करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल "बिना किसी कार्रवाई के किसी विधेयक को अनिश्चित काल तक लंबित नहीं रख सकते"। ऐसा करने पर, कोर्ट ने कहा कि "राज्यपाल एक अनिर्वाचित राज्य प्रमुख के रूप में एक विधिवत निर्वाचित विधायिका द्वारा विधायी डोमेन के कामकाज को वस्तुतः वीटो करने की स्थिति में होंगे"। न ही राज्यपाल, एक बार सहमति को रोक लेने के बाद, विधायिका द्वारा पुनः अधिनियमित विधेयक को और विलंबित करने के लिए राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई, हमारी संघीय राजनीति को प्रभावित करती है जो संविधान की मूल संरचना है। सच्चाई यह है कि कई राज्यों में राज्यपाल अपनी विवेकाधीन शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए राज्य सरकार के अनिर्वाचित विरोधी बन गए हैं। उन्होंने संविधान के "जितनी जल्दी हो सके" के स्पष्ट इरादे की व्याख्या इस अर्थ में करना शुरू कर दिया है कि वे इसे जितने लंबे समय तक चाहते हैं, उतना ही लंबा कर सकते हैं। ऐसे विधेयक हो सकते हैं, जिन पर राज्यपाल के पास पुनर्विचार या संशोधन का सुझाव देने के लिए उचित कारण हों, लेकिन इस विवेकाधीन शक्ति का उपयोग राज्य सरकार के शासन एजेंडे को बंधक बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है। विध ायी शक्ति सत्ता में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार के पास निहित है। राज्यपाल, एक अनिर्वाचित प्रहरी और राज्य के निष्पक्ष प्रमुख के रूप में, सरकार को अपने विचार दे सकते हैं, लेकिन उनके लिए विधि ावत पारित विधेयकों के न्यायाधीश और निष्पादक की स्थिति ग्रहण करना संविधान की स्पष्ट मंशा को लागू करना है, एक दुर्भावनापूर्ण और अलोकतांत्रिक अवरोध। इस रस्साकशी में, असली पीड़ित राज्य के लोग हैं, जिन्होंने एक ऐसी सरकार बनाने के लिए मतदान किया है जो अपने वादों को लागू कर सके और अपनी उम्मीदों पर खरा उतर सके। स्थिति वैसी ही है जैसी तब होती है जब सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम केंद्र सरकार को नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों की सूची की सिफारिश करता है। सिफारिशों को कार्यपालिका द्वारा ठुकराया नहीं जा सकता है, लेकिन सहमति के लिए कोई समय सीमा स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट नहीं की गई है, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि सरकार को सिफारिशों को अनिश्चित काल तक दबाए रखने से रोकने के लिए कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रवृत्ति पर प्रतिकूल ध्यान दिया है।

निराशा की फसल राजनीतिक अकाल का कारण बनेगी

संजय

कहावत है कि आप जो बोते हैं, वही काटते हैं। भारत के देहाती विस्तार में, जहाँ गांधी के भारतीय रहते हैं, किसान दुःख काट रहे हैं। मन का आंदोलन सड़क पर फैल रहा है। पिछले कुछ वर्षों से, किसान और उनके नेता भारी बारिश और चिलचिलाती गर्मी का सामना करते हुए सड़क पर सो रहे हैं। वे अब वोट बैंक नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे समाचार चक्र को प्रभावित करते हैं। पिछले हफ्ते, भाजपा की डायलॉग डेस्पराडो कंगना रनौत ने कहानी को खराब कर दिया। उन्होंने तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को लागू करने का आह्वान किया, जिन्हें मोदी सरकार ने 2021 के विरोध के बाद निरस्त कर दिया था। एक पहचान की तलाश में, उन्होंने भड़काऊ मांग कीरू "मुझे पता है कि यह बयान विवादास्पद हो सकता है, लेकिन तीन कृषि कानूनों को वापस लाया जाना चाहिए। किसानों को खुद इसकी मांग करनी चाहिए।" उनके अवलोकन को निरस्त किए गए कृत्यों को पुनर्जीवित करने के आध िकारिक प्रयास के रूप में देखा गया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पोस्ट करके सरकार की आलोचना कीरू "भाजपा विचारों का परीक्षण करती रहती है। वे किसी को जनता के सामने कोई विचार प्रस्तुत करने के लिए कहते हैं और फिर प्रतिक्रिया देखते हैं। ऐसा ही तब हुआ जब उनके एक सांसद ने किसान कानूनों को पुनर्जीवित करने की बात की, जो काले कानून थे। मोदीजी, कृपया स्पष्ट करें कि क्या आप इसके खिलाफ हैं या फिर आप फिर से शरारत करने वाले हैं।" 2020 में संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित, इन कानूनों का उद्देश्य कृषि बाजारों को विनियमित करना था ताकि किसानों को अपनी उपज गैर–आध िकारिक एजेंसियों को बेचने, थोक खरीदारों के साथ अनुबंध करने और भंडारण सीमा को हटाने की स्वतंत्रता मिले – ये सभी किसान की आय में वृद्धि करेंगे। लेकिन कृषकों ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने सरकार पर इस क्षेत्र को कॉर्पोरेट शोषण के लिए खोलने का आरोप लगाया। उन्होंने हिंसक विरोध प्रदर्शनों की एक श्रृंखला को जन्म दिया जिसमें 500 से अधिक लोग मारे गए। भारी बाधाओं के बावजूद तीन साल से लड़ाई चल रही है। नेता किसानों को अन्नदाता कहते हैं। लेकिन उनकी भूख मिटाने के लिए उनके पास कोई अन्न नहीं है। इसके बजाय, उन्हें आतंकवादी, देशद्रोही, राजनीतिक एजेंट करार दिया गया है और उनके आंदोलनकारी दृष्टिकोण के लिए उनका उपहास किया गया है। किसान अब वोट बैंक नहीं रहे जो सरकार बना सकें या हिला सकें, बल्कि वे विकास मॉडल के शिकार हैं जिसने भारतीय कृषि को हाशिए पर डाल दिया और इसे लाभ कमाने वाली बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बना दिया। भारत शायद अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत का अपवाद है। पिछले दो दशकों के दौरान, यह मुख्य रूप से कृषि आधारित अर्थव्यवस्था से बड़े पैमाने पर औद्योगिक विकास की मध्यवर्ती अवस्था से गुजरे बिना सेवा–संचालित अर्थव्यवस्था में बदल गया है। सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का योगदान 1990 में 35 प्रतिशत से गिरकर 2023 में लगभग 15 प्रतिशत रह गया है। जबकि भारत क्रय शक्ति के हिसाब से दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, इसकी प्रति व्यक्ति कृषि आय एक शहरी भारतीय की आधी है। 60 प्रतिशत से अधिक आबादी राष्ट्रीय आय के 15 प्रतिशत पर रहती है। इसके अलावा, नवीनतम आर्थिक सर्वेक्षण कहता है कि कृषि विकास 2022–23 में 4.7 प्रतिशत से 2023–24 में 1.4 प्रतिशत तक तेजी से गिर गया है। उचित रूप से, ग्रामीण नेता यह वैध सवाल उठा रहे हैं कि यदि शेयर बाजार के साथ–साथ सेवा क्षेत्र भी विकास के सभी रिकॉर्ड तोड़ सकता है, तो कृषि क्यों पीछे रह गई? भारतीय सेवा क्षेत्र जिसमें विमानन, प्रौद्योगिकी, वित्त आदि शामिल हैं, सकल घरेलू उत्पाद में 58 प्रतिशत से अधिक का योगदान देता है, जो शायद 10 प्रतिशत से भी कम भारतीयों की जेब में जाता है। इसके अलावा, भारतीय किसान बढ़ती इनपुट लागत, कृषि उत्पादों के आयात और प्रकृति की अनिश्चितताओं से मुश्किल में पड़ गया है। यहां तक घ्कि पैमाने का अर्थशास्त्र भी किसानों के खिलाफ है। जोतों के विखंडन ने खेती को घाटे का सौदा बना दिया है। नवीनतम भूमि–जोत सर्वेक्षण के अनुसार, लगभग 70 प्रतिशत कृषि परिवारों के पास 1 हेक्टेयर से भी कम भूमि है।

पिछले एक दशक के दौरान, मोदी सरकार ने इस गिरावट को रोकने के लिए मजबूत वित्तीय और प्रशासनिक कदम उठाए हैं। इसने किसानों को उनकी गेहूं और धान की फसल खरीदने के लिए 18 लाख करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया है। इसने उर्वरक सब्सिडी पर 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए हैं, बड़े पैमाने पर प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण किए हैं और उत्पादकता में सुधार और ग्रामीण आबादी के लिए बेहतर आवास सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं।

लेकिन किसानों की आय दोगुनी करने का इसका वादा अधूरा रह गया है–मुख्यतः इसलिए कि खेत जोतना उतना आकर्षक पेशा नहीं है जितना कि मोबाइल आधारित नए शानदार अवसर हैं। अर्थशास्त्री किसानों की दयनीय दुर्दशा के लिए आंशिक रूप से सरकारों और उसकी एजेंसियों से मिलकर बने प्रतिष्ठान के निगमीकरण को जिम्मेदार ठहराते हैं। विदेश में शिक्षित नीति निर्माता भारतीय कृषि को किसी अन्य कॉर्पोरेट पहचान की तरह ही मानते रहे हैं। वे ऐसे उपाय सुझाते हैं जो बैंकिंग, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी और बड़ी खाद्य कंपनियों जैसे क्षेत्रों के लिए मांग पैदा करते हैं। लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी 70 प्रतिशत भूमि जोतने वालों के पास सुनिश्चित सिंचाई का अभाव हैय न तो राज्यों और न ही केंद्र ने उचित जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विशाल नहर प्रणाली की योजना बनाई है। जबकि सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र और स्टार्टअप के लिए उत्पादकता से जुड़े प्रोत्साहन पेश किए हैं, लेकिन नवोन्मेषी किसानों के लिए कोई आकर्षक मौद्रिक प्रोत्साहन नहीं है।

डीएम की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। डीएम चन्द्र विजय सिंह की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति की बैठकद सम्पन्न हुई।बैठक में सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड–2 मानिक चंद्र सिंह ने बताया कि खाद्य पदार्थो पर प्रवर्तन कार्यवाही के तहत वित्तीय वर्ष 2023–24 में 2939 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 327 प्रतिष्ठानों पर छापे की कार्यवाही की गई।इस कारवाई में 417 खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया।270 जाँच रिपोर्ट प्राप्त में 152 खाद्य पदार्थ मानक के विपरीत पाये गये। अभियोजन कार्यवाही के अन्तर्गत 228 वाद मा0 न्यायालय में योजित किये गये एवं न्यायालय द्वारा आलोच्य अवधि में 247 वादों का निर्णय किया गया।जिसमें कुल 6981000/– मात्र का अर्थदण्ड लगा।वित्तीय वर्ष 2024–25 माह अगस्त 2024 तक 1272 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हुये 138 छापे की कार्यवाही में 172 खाद्य पदार्थो के नमूनें संग्रहित किये गये। उक्त अवधि में 262 जाँच रिपोर्ट प्राप्त हुयी जिसमें 145 खाद्य पदार्थ मानक के विपरीत पाये गये तथा अभियोजन कार्यवाही के अन्तर्गत 164 वाद मा0 न्यायालय में योजित किये गये एवं मा0 न्यायालय द्वारा आलोच्य अवधि में 115 वादों का निर्णय किया गया।जहां कुल 3552000/– मात्र का अर्थदण्ड अधिरोपित कराया गया। बैठक में न्यायालय सम्बन्धी कार्यवाही, विभिन्न न्यायालयों में वादों की पैरवी की स्थिति विभाग द्वारा जारी किये गये लाईसेन्सध्पंजीकरण की अद्यतन स्थिति तथा खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की योजनाओं के अन्तर्गत जनपद में कराये गये कार्यक्रमों का विवरण प्रस्तुत किया गया।सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड–2 द्वारा समिति को अपना एजेंडा प्रस्तुत कर अवगत कराया गया कि एक स्ट्रीट फूड हब जनपद में प्रस्तावित है। जिसके लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा 1 करोड़ रूपये की धनराशि नगर निगम को प्रदान किये हुए एक वर्ष का समय हो चुका है परन्तु इस सम्बन्ध में कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। बैठक में जिलाधिकारी ने निगम के प्रतिनिधि को निर्देशित किया कि इस सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही करते हुए एक सप्ताह में कार्य अवश्य प्रारम्भ कर दिया जाये। आई0आई0ए0 के अध्यक्ष द्वारा होटल बुकिंग तथा खान पान के सम्बन्ध में ओवर प्राइसिंग किये जाने का प्रकरण समिति के संज्ञान में लाते हुए मानक तय किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।जिस पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा वरिष्ठ निरीक्षक बाट व माप तथा सहायक आयुक्त (खाद्य)–प्प् को इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।जिलाधिकारी द्वारा विभाग को प्रवर्तन कार्य अधिक कुशलता से किये जाने पर बल दिया गया।जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि एम0डी0एम0, पी0डी0एस0 एवं आई0सी0डी0एस0 के फूड हैण्डलर्स के लाईसेंस एवं पंजीकरण के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग तत्काल आवश्यक कार्यवाही करते हुए लाईसेंस/पंजीकरण निर्गत कराना सुनिश्चित करें। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिलापूर्ति अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, जिला पंचायती राज्य अधिकारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उपायुक्त उद्योग, सहायक नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी, औषधि निरीक्षक, विभागाध्यक्ष गृह विज्ञान साकेत महाविद्यालय, सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि, व्यापारिक एवं उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि के रूप में श्री शिवबक्श सिंह तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के समस्त अधिकारीगण उपस्थित रहे।

सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के सम्मान में आयोजित हुआ सम्मान समारोह

अयोध्या। व्यक्ति कभी भी सेवानिवृत्त नहीं होता है।हां इतना जरूर है कि कोई सरकारी व गैर सरकारी नौकरी व संस्था से सेवानिवृत्त हो जाता है। परंतु पारिवारिक जिम्मेदारियों व सामाजिक कार्यों से मुक्त नहीं होता है।यह बातें सोमवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित सेवानिवृत्त पुलिस कर्मियों के सम्मान में आयोजित विदाई समारोह में मुख्य अतिथि के रुप में एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने कही। बताते चलें उप निरीक्षक तेजबहादुर सिंह,उप निरीक्षक बालकृष्ण शुक्ला,उप निरीक्षक लाल जीध के साथ मुख्य आरक्षी चालक विजय कुमार शुक्ला सेवानिवृत्त हुए थे। इस मौके पर मुख्य अतिथि एसपी ग्रामीण बलवंत चौधरी ने सेवा निवृत्त होने वाले पुलिस कर्मियों को स्मृति चिन्ह,शाल राम चरित मानस,छाता आदि वस्तुएं देकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया।इस मौके पर सीओ योगेन्द्र कुमार व अन्य अधिकारी व पुलिस कर्मी मौजूद रहे।

व्यापारी वर्ग समाज के आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक भविष्य के निर्माण में एक सशक्त स्तंभ है - रजनी तिवारी

हरदोई (अम्बरीष कुमार सक्सेना) शाहाबाद विधान सभा क्षेत्र के मो. चौक स्थित गायत्री मंदिर में व्यापारी बंधुओं द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि कहा कि व्यापारी समाज देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ है। व्यापारी समाज की पूंजी निवेश में बड़ी हिस्सेदारी है।व्यापारी समाज अपने सामाजिक कार्यों के लिए भी बड़ी पहचान रखता है। कहा कि व्यापारी वर्ग समाज के आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक भविष्य के निर्माण में एक सशक्त स्तंभ है। उन्होंने कहा कि व्यापारी समाज को भाजपा सरकार में अनेक सुविधाएं मिल रही हैं फिर भी व्यापारियों की समस्याओं की जानकारी सरकार को देना जरूरी है।ताकि समय पर उनकी समस्याओं का समाधान हो सके।उन्होंने न सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास,सबका प्रयास आदर्श वाक्य से निर्देशित होकर विकसित उत्तर प्रदेश के माध्यम से विकसित भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध होने का आह्वान किया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के सक्षम नेतृत्व में, देश में विनिर्माण क्षेत्र ने महत्वपूर्ण परिवर्तन का अनुभव किया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधान मंत्री ने ष्उन्नत और विकसित भारतष् के मंत्र को बढ़ावा दिया है, और कृषि, सेवाओं और उद्योग में समग्र विकास ने विकसित भारत को प्राप्त करने में राष्ट्रीय हित की मजबूत भावना को बढ़ावा दिया है। जिसके कारण भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मंत्री व्यापारियों के हित में सदैव सहयोग देने का अश्वासन दिया। उन्होंने सम्मानित करने के लिये समस्त व्यापारी बन्धुओं का हार्दिक आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से व्यापार मण्डल के संरक्षक डा. मुरारीलाल गुप्ता ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा व्यापारियों की दुकानें उजड़ने से बचाने के लिए किये गए उनके द्वारा किये गए प्रयासों की सराहना करते हुए आभार जताया। सीमेंट व्यवसायी विनोद प्रकाश गुप्ता , व्यापार प्रकोष्ठ के जिला संयोजक नवनीत गुप्ता , सर्राफा व्यवसायी मनोज रस्तोगी लालू,पवन रस्तोगी, व्यापार मण्डल के नगर अध्यक्ष सर्वेश गुप्ता, कपड़ा व्यवसायी शिव कुमार गुप्ता, सत्य प्रकाश गुप्ता सभासद प्र. राकेश गुप्ता मंगू आदि ने उच्च शिक्षा राज्य मंत्री का फूल मालाओं से लादकर, स्मृति चिन्ह् भेंटकर एवं शाल आदि भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल पाण्डेय पिन्टू सत्येंद्र श्रीवास्तव, सुभाष रस्तोगी, प्रमोद रस्तोगी, छुन्ना भाई, संजीव बांगा, सुभाष सिंह, कमल सिंह,आजाद सिंह, अमित मिश्र, हरि मिश्र, वैभव पाठक तथा वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। समापन पर भाजपा नेता नवनीत गुप्ता ने व्यापारियों की ओर से उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी का आभार व्यक्त किया।

जिलाधिकारी ने भरतकुण्ड का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए निर्देश

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने सोमवार को भरतकुण्ड का निरीक्षण करते हुये वहां पर मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए।इस मौके पर उन्होंने कुण्ड की साफ सफाई, घाट को पक्के करना, ग्रीन एरिया,महिला शौचालय आदि को देखा गया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कुण्ड के पार्क में छोटे छोटे पौधे लगाने, कुण्ड के चारों तरफ रेलिंग बड़ी करने व समुचित प्रकाश की व्यवस्था करने तथा कुण्ड के गंदे पानी की नियमित साफ–सफाई के लिए के निर्देश सम्बंधित अधिकारियों को दिये।उन्होंने भरतकुण्ड में आने वाले श्रद्वालुओं के लिए विश्राम हेतु टीन शेड व पेयजल की व्यवस्था करने के साथ ही कुण्ड के पत्थरों व सीढ़ियों पर जमी काई की साफ सफाई करने के निर्देश दिये।उन्होंने कहा कि सभी सम्बंधित कार्यो को यथाशीघ्र पूर्ण किया जाय।इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन अनिरूद्व प्रताप सिंह, उपजिलाधिकारी सोहावल अशोक कुमार सैनी सहित उपनिदेशक पर्यटन, अधिशाषी अभियन्ता, प्रधान व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।

विधि–विधान सहित सम्पन्न हुआ अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन

अयोध्या। सोमवार को अयोध्या की रामलीला का भूमि पूजन विधि विधान सहित संपन्न हुआ।इस मौके पर विशेष अतिथि राजीव कुमार उपस्थित रहे।भूमि पूजन कार्यक्रम में कार्यक्रम में अयोध्या की रामलीला कमेटी के फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक (बॉबी) व फाउंडर महासचिव शुभम मलिक ने कहा कि आज अयोध्या की रामलीला के छठे संस्करण के भूमि–पूजन का कार्यक्रम विधि–विधान सहित पूरा हुआ है। जो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि अयोध्या की रामलीला को इतने बरस हो गए हैं पता ही नहीं चला। अयोध्या की रामलीला भगवान श्री राम और भगवान बजरंगबली के आशीर्वाद से संपन्न होती है।फाउंडर अध्यक्ष सुभाष मलिक और महासचिव शुभम मलिक ने बोला अयोध्या की रामलीला आज विश्व की सबसे बड़ी रामलीला है और इसे विश्व की सबसे बड़ी रामलीला राम भक्तों ने बनाया है। हमारा अयोध्या की रामलीला करने का एक ही उद्देश्य रहता है जो राम भक्त घर बैठ कर देखते हैं उनको एक सुंदर रामलीला दिखाएं और हर वर्ष हमारी कोशिश रहती है कि अयोध्या की रामलीला और अच्छे से अच्छा दिखाए। अयोध्या की रामलीला पिछले साल 36 करोड़ से ज्यादा राम भक्तों ने अपने घरों में बैठकर देखा था। अयोध्या की रामलीला का जन्म कोरोना काल में हुआ था। इसकी अनुमति मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दी थी।एक समय था जब पूरी दुनिया में एकलौती अयोध्या में यह रामलीला सम्पन्न हुई थी जब कोरोना काल में जिसको हर वर्ष दूरदर्शन दिखाता है। इसी तरह इस वर्ष भी दूरदर्शन पर यह रामलीला देखा जा सकता है। हर साल की भांति अयोध्या की रामलीला का इस वर्ष छठा संस्करण 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर को पूरा होने जा रहा है।जिसमें देश भर से कई क्षेत्रों से हस्तियां अयोध्या की रामलीला देखने भगवान राम के जन्म भूमि अयोध्या में पधारेंगे।

अखिल भारतीय बढ़ई महासभा द्वारा विशाल सामाजिक सम्मेलन संपन्न हुआ

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। विश्वकर्मा राणा समाज के प्रधान समाजसेवी श्री उमेश प्रसाद राणा जी आज विशिष्ट अतिथि के रूप में सहकारिता भवन हजरतगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय बढ़ई समाज के कार्यक्रम का शोभा बढ़ाते हुए इस समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विश्राम शर्मा जी, विश्वकर्मा समाज के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र श्री इंद्रजीत सिंह जी के साथ मंच शेयर करते हुए मंच पर अपने विचार को रखते हुए इन्होंने कहा कि हमारे समाज राजनीतिक क्षेत्र में उपेक्षित हो रहा है स हमसे अन्य समाज का कम आबादी होने के बावजूद भी राजनीतिक भागीदारी में आगे बढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग को निरंतर सामाजिक कार्यक्रम कर सरकार तक अपने संदेश को पहुंचना है और राजनीतिक भागीदारी का अधिकार लेना है स अपने समाज को संवैधानिक समानता के अधिकार दिलाने के साथ–साथ अपने समाज को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करने की आवश्यकता है इसमें हमारे तमाम महिलाये,समाज सेवी, बुद्धिजीवी लोग आगे आकर अपनी सहभागिता निभाएं जिससे अपना समाज सशक्त होगा । यथाशीघ्र श्री उमेश राणा जी के देखरेख में देश की राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। झारखंड गिरिडीह जिले के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे एक छोटे से गांव सिंघो पंचायत तिसरी के रहने वाले श्री उमेश प्रसाद राणा जी आज अपने समाज हित की बात राष्ट्रीय स्तर पर रखते हुए वर्तमान सरकार तक अपनी आवाज पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं स क्षेत्र के लिए यह बहुत ही गर्व की बात है इसमें तमाम अपने क्षेत्र के कई राजनीति एवं समाजसेवी सुजीत पाण्डेय जी , बिरजू राणा जी अरुण मिस्त्री जी, भोला मिस्त्री जी संजय कुमार जी सुनील जी एवं अन्य कई लोग इन्हें बधाई दिए स साथ ही अपने क्षेत्र पहुंचने का इनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है जहां गर्मजोशी से अपने समाज द्वारा इनका भव्य स्वागत किया जाएगा।

वार्षिक प्रांतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया

ब्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय

बांदा। श्री हनुमान लाज बड़ा बाईपास नजदीक पेट्रोल पंप , वार्षिक प्रांतीय प्रतिनिधि सभा का आयोजन किया गया जिसमे 14 जिलों के अध्यक्ष सचिव एवं दो देश हित में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सदस्य आए। कानपुर के प्रांतीय अध्यक्ष कर्नल बीएस राठौर, उपाध्यक्ष मेजर वीरेंद्र सिंह तोमर, ने सर्व प्रथम दीप प्रज्ज्वलित कर मां भारती को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए ने हमरे बीच नही रहे सदस्यों को यादकर दो मिनट का मौन रखा और जूनियर हाईस्कूल के बच्चों ने आए हुए आगंतुकों को सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, और देश भक्ति गीतों से विभिन्न जनपदों से आए सभी महानुभावों का मन मोहा, उसके बाद प्रांतीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष ने आपने उद्बोधन में पूर्व सैनिकों को अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए, और समाज की कुरीतियों जैसे नशा मुक्ति, कन्याओं एवं बालिकाओं को समाज के दो पैर वाले भेड़ियों से बचाने का आवाहन किया और सैन्य परिवार को संगठित रहने का मंत्र दिया सैनिकों को विद्यालय जा कर बच्चों को देश भक्ति के गुण सीखाने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद विभिन्न जनपदों से आए हुए हुए टीम को सम्मानित करते हुए अपने अपने जनपदों में देश हित सर्वोपरि रखने के लिए मंत्र दिया। हमीरपुर अध्यक्ष हवलदार देवेश खरे जी, सुबेदार पुष्पेंद्र भदौरिया जी प्रांतीय महासचिव, सुबेदार मेजर हरिमोहन सिंह, बांदा अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के अध्यक्ष कप्तान श्यामबाबू सिंह राठौर, सचिव सूबेदार मेजर दयाशंकर तिवारी, सुबेदार छत्रपाल परिहार, मंच संचालक सूबेदार आर पी तिवारी, मीडिया प्रभारी सूबेदार मेजर रामनरेश सिंह सेंगर, विशिष्ठ करकर्ता कप्तान विजय कुमार कुशवाहा, कोषाध्यक्ष सूबेदार सीताराम तिवारी, अग्निवीरों को निःशुल्क प्रशिक्षण देने वाले सूबेदार वीरेंद्र सिंह, बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष राजू सिंह फौजी, पूर्व तिंदवारी नगर अध्यक्ष भूरेलाल फौजी, जनपद की वीर नारी रन्नो देवी, मात्र शक्ति एवं लगभग 200 पूर्व सैनिकों ने प्रतिभाग किया। 2 बजे खुले मंच से चर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबके बाद परिवाद सुनने के बाद अध्यक्ष कर्नल राठौर ने प्रांतीय सभा को शायं 04रू30 बजे सभा को समाप्त करने की घोषणा की। आयोजन को भव्य और दिव्या बनाने के लिए अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद बांदा इकाई की प्रांतीय अध्यक्ष ने भूरि भूरि प्रसंशा की और सहयोग राशि में 10,000/ रुपए का अनुदान भी किया।

पाली में एसडीएम की अध्यक्षता में हुआ थाना समाधान दिवस'

'ब्यूरो रिपोर्ट–जनार्दन श्रीवास्तव'

'पाली–(हरदोई)' पाली थाने पर एसडीएम की अध्यक्षता में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। समाधान दिवस पर पहुँचे सवायजपुर एसडीएम संजय कुमार अग्रहरि ने थाना प्रभारी निरीक्षक के साथ जन शिकायतों को बड़ी गंभीरता से सुना। इस दौरान आई शिकायतों में से कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित को समय सीमा के अंतर्गत निस्तारित करने हेतु निर्देशित किया गया।उपजिलाधिकारी सवायजपुर संजय कुमार अग्रहरि की अध्यक्षता में आयोजित समाधान दिवस में प्रभारी निरीक्षक रमेशचंद्र पाण्डेय ने आये हुए फरियादियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना।और कुछ शिकायतों को मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया।उपजिलाधिकारी संजय कुमार अग्रहरि ने राजस्व कर्मियों को निर्देशित करते हुये कहा कि क्षेत्र में जहाँ कहीं भी भूमि विवाद हो वहाँ पुलिस एवं राजस्व कर्मी संयुक्त टीम के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर भूमि से संबंधित विवादों का निस्तारण प्रमुखता से करें।उन्होंने कहा कि भूमि विवाद दे संबंधित कोई भी प्रकरण ज्यादा समय तक लंबित न रखा जाए। वहीं प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पाण्डेय ने कहा कि भूमि विवादों का निपटारा करने के लिए जहाँ कहीं भी पुलिस बल की आवश्यकता है,वहाँ तत्काल राजस्व कर्मियों को पुलिस बल मुहैया कराया जायेगा। इस मौके पर कस्बा इंचार्ज शिवशंकर मिश्रा सहित राजस्व विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे।

एसडी मेमोरियल जाना बाजार ने किया सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल,गोल्फ सिटी,लखनऊ रहा स्किल एक्सपो में उत्कृष्ट प्रदर्शन

अयोध्या। सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल, गोल्फ सिटी, लखनऊ में आयोजित स्किल एक्सपो में एसडी मेमोरियल, जाना बाजार ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।एक्सपो छात्रों में व्यावसायिक कौशल और नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था,जिसमें उत्तर भारत के इलाहाबाद मंडल के सभी सीबीएसई स्कूलों ने हिस्सा लिया।इस कार्यक्रम का आयोजन लाइफोलॉजी और सीबीएसई,नई दिल्ली की स्किल डिवीजन द्वारा किया गया था, जिसमें छात्रों को विभिन्न आधुनिक कौशलों से अवगत कराया गया।एसडी मेमोरियल, जाना बाजार के छात्रों ने अपने स्कूल की ओर से कई रोचक और उपयोगी परियोजनाओं का प्रदर्शन किया।इन परियोजनाओं में तकनीकी नवाचार, आर्ट्स और हस्तशिल्प के साथ–साथ समाज सेवा से संबंधित कार्य भी शामिल थे। प्रतिभागियों ने इस मंच का उपयोग करके अपनी रचनात्मकता और क्षमताओं का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।स्कूल के प्रबंधक और शिक्षकों ने कहा, ष्इस तरह के आयोजनों से छात्रों को न केवल अपने कौशल दिखाने का मौका मिलता है, बल्कि उन्हें वास्तविक जीवन की समस्याओं के समाधान खोजने के लिए प्रेरणा भी मिलती है।यह एक्सपो सेठ आनंद राम जयपुरिया स्कूल में आयोजित किया गया था,जिसमें स्किल डिवेलपमेंट को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया। कार्यक्रम ने छात्रों को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए तैयार होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान को सफल बनाने के लिए बैठक सम्पन्न

(डॉ अजय तिवारी
जिला संवाददाता)

अयोध्या। सोमवार को विशेष संचारी रोग नियंत्रण को सफल बनाने के लिए सीडीओ की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में सम्पन्न हुई।बताते चलें कि मंगलवार यानी कि 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर व दस्तक अभियान 11 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक जनपद में संचालित किया जाएगा।इस अभियान को सफल बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सभी संबंधित विभागों की जनपद स्तरीय अंतर्विभागीय समन्वय समिति की द्वितीय बैठक का आयोजन कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया था। बैठक में सीएमओ डॉ संजय जैन,नगर स्वास्थ्य अधिकारी,जिला मलेरिया अधिकारी,जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवम सूचना अधिकारी,डी पी एम,सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अधीक्षक सहित अन्य पदाधिकारी व कर्मी मौजूद रहे।

किसानों के लिए आफत बनी बारिश– यहां धान की फसल को हुआ भारी नुकसान

सुल्तानपुर, बल्दीराय– बीते दो दिनों से लगातार बारिश जारी है. इसकी वजह से किसानों के सामने भारी मुसीबत खड़ी हो गई है। वहीं जहाँ तापमान में गिरावट आने से लोगों को गर्मी से निजात मिली है. तो वहीं इस बारिश के चलते खरीफ फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। क्षेत्र के कई गांवों में बारिश की मार से धान की फसल जमीन पर लेट गई है, जिससे पकी फसल के दाने अब अंकुरित हो रहे है, जिससे किसानों के सामने जीवनयापन का संकट खड़ा हो गया है। कुछ ऐसा ही दरियापुर निवासी किसान अमरनाथ मौर्य के साथ देखने को मिला किसान द्वारा धान की लगभग एक एकड़ अगैती खेती की गई थी, जिसकी वजह से लगभग फसल पूरी पककर कटने के कगार पर पहुंच चुकी थी पर हथिया (हस्त) नक्षत्र के लगते ही बरसात लगातार होने लगी जिसकी वजह से उनकी धान की फसल पूरी तरह से जमीन पर गिर गई है जिसमें मिट्टी की नमी के कारण जमाव होना शुरू हो गया है। अब ऐसे में फसल को सुरक्षित और संरक्षित करने का कोई विकल्प नही है जो की बढ़िया उपज में संकट का कारण बन गया है।

बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद कार्यकारिणी का चुनाव सम्पन्न

निर्विरोध चुनाव में अध्यक्ष महेंद्र तिवारी, महासचिव कैलाश जैन और वरिष्ठ उपाध्यक्ष बने महेंद्र भीष्म

मृत्युंजय प्रताप सिंह

लखनऊ। बुंदेलखंड सांस्कृतिक एवं सामाजिक सहयोग परिषद कार्यकारिणी का चुनाव रविवार को हिंदी संस्थान के निराला सभागार में चुनाव अधिकारी बनारसी प्रसाद की देखरेख मे सम्पन्न हुआ। निर्विरोध संपन्न हुए चुनाव में निम्न कार्यकारणी गठित हुई।

जिसमे अध्यक्ष महेंद्र तिवारी, महासचिव कैलाश जैन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेंद्र भीष्म, उपाध्यक्ष सुरेंद्र अग्निहोत्री, डा के पी प्रजापति ,बृजेंद्र लिटोरिया, जितेंद्र तिवारी, अनीता जैन ,कोषाध्यक्ष गणेश शंकर गुप्ता, सांस्कृतिक सचिव अर्चना गुप्ता ,प्रचार सचिव आलोक जैन, लेखा परीक्षक रजनी विश्वकर्मा, सचिव योगेश चौहान, लखन द्विवेदी, सुधीर गुप्ता एवं दस सदस्य निर्विरोध चुने गए।

सभी सदस्यों ने एक दूसरे को बधाई दी एवं एकजुट होकर संस्था को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आम सभा में वरिष्ठ सदस्य श्री एवं बुंदेलखंड संस्था के सभी सदस्य मौजूद रहे।

संवेदनशीलता व शीघ्रता करें जन समस्याओं का निस्तारण, लापरवाही पर कार्रवाई तय

गोरखपुर, संवाददाता। गोरखपुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में आए लोगों से मुलाकात की। ध्यानपूर्वक उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को निर्देशित किया कि जन समस्याओं का समाधान शीघ्रता से किया जाए, इसमें किसी भी तरह की शिथिलता या लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हर समस्या का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और संतुष्टिपरक होना चाहिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि जनता की हर समस्या का समाधान सरकार की प्रमुख प्राथमिकता है और इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता अक्षम्य होगी। गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में आयोजित जनता दर्शन में कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और एक–एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने करीब 200 लोगों से मुलाकात की। उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित निस्तारण का निर्देश देने के साथ मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर पीड़ित की समस्या का समाधान कराने के लिए दृढ़ संकल्पित है। उन्होंने अधिकारियों को यह भी हिदायत दी कि किसी की जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले, कमजोरों को उजाड़ने वाले किसी भी सूरत में बख्शे न जाएं। उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के समक्ष जनता दर्शन में कई लोग इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार लेकर पहुंचे थे। सीएम योगी ने उन्हें आश्वस्त किया कि सरकार इलाज के लिए भरपूर मदद करेगी। उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को हस्तगत करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इलाज से जुड़ी इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण करा कर शासन में उपलब्ध कराया जाए। इस दौरान उन्होंने सभी पात्रों को आयुष्मान योजना से आच्छादित करने के भी निर्देश अफसरों को दिए। जनता दर्शन में आए राजस्व व पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए उसकी सहायता की जानी चाहिए। शनिवार देर शाम गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रविवार सुबह की दिनचर्या परंपरागत रही। हर बार की तरह उन्होंने प्रातःकाल गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरखनाथ का दर्शन–पूजन किया और अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका। इसके बाद मंदिर परिसर का भ्रमण करने निकले। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री की नजर परिजनों के साथ मंदिर में दर्शन पूजन करने आए बच्चों पर पड़ी।

बारिश ने तोड़ा 95 वर्ष का रिकार्ड, जन निकाली के इंतजाम फेल- रिकार्ड 168.1 एमएम हुई बारिश

गोरखपुर, संवाददाता। हथिया नक्षत्र में बीते तीन दिनों से हो रही झमाझम बारिश ने शनिवार को जिले में पिछले 95 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बीते 24 घंटे में 168.1 मिली मीटर बारिश दर्ज की गई है। सितंबर में इससे पहले वर्ष 1930 में एक दिन में 175 मिमी बारिश हुई थी, जो अब तक का रिकॉर्ड है। लगातार इतनी ज्यादा बारिश होने से जल निकासी के सारे इंतजाम फेल हो गए। शहर की प्रमुख सड़कों और गलियों में लबालब पानी भर गया। लेकिन नालों की सफाई होने और जगह–जगह पंपसेट और जलनिकासी के लिए हुए इंतजाम बारिश के बंद होते ही सभी प्रमुख सड़कों से बारिश का पानी हट गया। लगातार हो रही बारिश से दिन का तापमान लुढ़क कर सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे 24.9 डिग्री सेल्सियस आ गया है, जो पिछले 35 वर्षों में सबसे कम है। इसलिए पंखे की तेज हवा से भी ठंड लग रही है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक गुजरात से लेकर उत्तर पश्चिम बिहार से होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक एक ट्रफ लाइन गुजर रही है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 18000 फीट की ऊंचाई पर चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। यह दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इन दोनों का असर पूर्वी यूपी पर बना हुआ है। इसके चलते निम्न वायु दाब बना हुआ है और बारिश हो रही है। बृहस्पतिवार की शाम तक 7.8 मिली मीटर बारिश हुई थी।

शुक्रवार की शाम तक जिले में करीब 100.2 मिली मीटर बारिश हुई। जबकि, शनिवार की शाम 5 बजे तक 24 घंटे में 168.1 मिली मीटर बारिश हुई। इससे पहले वर्ष 2007 में 26 सितंबर को 24 घंटे में 149.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी। झमाझम बारिश से दिन और रात का तापमान नीचे लुढ़क गया है। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया। शनिवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 2.4 डिग्री नीचे रहा।

मंगलवार तक ऐसा ही रह सकता है मौसम

मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले तीन दिनों में करीब 276 मिली मीटर बारिश हो चुकी है। जबकि सितंबर को मानसून सीजन के समाप्ति का महीना माना जाता है। इस महीने में औसतन 178 मिमी बारिश ही होती है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी मंगलवार तक मौसम ऐसे ही बना रहेगा। रुक–रुक बारिश होगी।

दिन के तापमान में आई गिरावट, टूटा 35 वर्ष का रिकार्ड

शनिवार को हुई झमाझम बारिश के चलते दिन का तापमान लुढ़क कर सामान्य से 8 डिग्री सेल्सियस नीचे चला गया। दिन का अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यह पिछले 35 वर्षों में सबसे कम है। वर्ष 1990 में न्यूनतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। इस माह में ही अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। जो 30 वर्षों में सर्वाधिक था।

संक्षिप्त खबरें

गोरखनाथ में ट्रक की चपेट में आने से मजदूर की मौत

गोरखपुर, संवाददाता। गोरखनाथ इलाके में 10 नंबर बोरिंग के पास फोरलेन हाईवे पर रविवार की भोर में ट्रक की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान की कोशिश की, लेकिन शिनाख्त नहीं होने पर मोर्चरी में रखवा दिया। गोरखनाथ पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 45 वर्ष के आसपास रही होगी। रविवार की भोर में करीब चार बजे वह हाईवे के पास मौजूद था। इस दौरान ट्रक की चपेट में आ गया। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर फरार हो गया। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के पहचान की कोशिश की। लेकिन, उसकी शिनाख्त न होने पर शव को मोर्चरी में रखवा दिया।

संदिग्ध हालात में विवाहिता की मौत, हत्या का आरोप

गोरखपुर, संवाददाता। गगहा इलाके के टिकरी गांव में विवाहिता की मौत के मामले में मायकेवालों ने ससुरालियों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है। मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पिता की तहरीर पर पुलिस ने पति, सास व जेठानी पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दिया है। जानकारी के मुताबिक, टिकरी गांव के विशाल की शादी 17 जून 2023 को बांसगांव के मड़ई निवासी रामसागर की बेटी निगम (25) के साथ हुई थी। शनिवार रात खाना खाने के बाद पति पत्नी अपने कमरे में चले गए। रविवार सुबह पत्नी का शव कमरे में फंदे से लटकते मिला। मायके पक्ष का आरोप है कि दहेज की खातिर पति और ससुराल के लोग पुत्री को प्रताड़ित करते थे। ससुरालियों पर पुत्री की हत्या का आरोप लगाया गया। मृतका के पिता रामसागर की तहरीर के आधार पर पति, सास और जेठानी पर केस दर्ज किया गया है। गगहा पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कुशीनगर पहुंची एनआईए टीम

कुशीनगर, संवाददाता। कुशीनगर पडरौना में जाली नोट के साथ 11 लोगों की गिरफ्तारी और इस मामले के विदेश कनेक्शन मिलने के बाद शनिवार को एनआईए की टीम कुशीनगर पहुंची। तमकुहीराज कस्बे में लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस अधिकारियों से भी गिरोह के संबंध में टीम ने इनपुट लिया। पिछले दिनों एटीएस की टीम स्थानीय पुलिस और तमकुहीराज कस्बे में लोगों से पूछताछ कर चुकी है। तमकुहीराज कस्बे के सपा नेता रफी खान उर्फ बबलू समेत दस लोगों को पुलिस ने जाली नोट, नेपाली करेंसी, अवैध असलहा और बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा था। रफी खान के गैंग के एक गुर्गे को बाद में मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया। उसके पास से भी जाली नोट बरामद हुए थे। मामला नेपाल से जुड़ा होने और कई गैर कानूनी गतिविधियों में आरोपियों के शामिल होने के संकेत मिलने के बाद एटीएस और एनआईए की टीम सक्रिय हो गई। पुलिस से कार्रवाई की पूरी जानकारी लेने और दो दिन तक छानबीन के बाद शुक्रवार को एटीएस की तीन सदस्यीय टीम वापस गई। शनिवार को एनआईए की टीम पहुंची। एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि पूरी कार्रवाई की जानकारी जांच एजेंसियों को सौंप दी गई है। एजेंसियां अपने स्तर से जांच कर रही हैं।

बुनकरों की बिजली बिल समस्या को लेकर कैट ने प्रधानमंत्री को भेजा पत्रक

वाराणसी, संवाददाता। काशी समेत यूपी के बुनकरों के बिजली बिल में हुए अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल के जरिये प्रधानमंत्री को पत्रक भेजा है। प्रदेश महामंत्री अखिलेश कुमार मिश्र के नेतृत्व में बुनकरों ने सांसद को पत्रक सौंपा।

वाराणसी के चांदपुर निवासी अखिलेश कुमार मिश्र ने बताया उत्तर प्रदेश के वस्त्र बुनकरों को किसानों की भांति विद्युत प्रतिपूर्ति योजना तत्कालीन प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2006 में शासनादेश में पावरलूम बुनकारों को फ्लैट रेट पर 150 किलोवाट की सीमा तक कराई जाने योजना शुरू किया गया था, जिसको अमान्य करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी पावरलूम बुनकर फ्लैट रेट लागू किया गया था, जिसमे 5 किलोवाट तक निर्धारित किया गया था, जो पूर्णतः अव्यवहारिक है। अब 5 किलो वाट बिजली बिल में 30 गुना मूल्य वृद्धि किया गया है, जो न्यायसंगत नहीं है। एक ही प्रकार के वस्त्र निर्माण पर दो श्रेणी के लोगों के लागत मूल्य में बहुत ज्यादा अंतर आ रहा है।

अब 5 किलो वाट से ज्यादा विद्युत घर वाले बुनकरों के वस्त्र बिकना नामुमकिन हो रहा है। इस स्थिति में उनके सामने अपने रोजगार को बंद करने के अलावा अन्य कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। पत्रक सौंपने वालों में वाराणसी जिलाध्यक्ष श्याम सुंदर गुप्ता, पंकज अरोरा, महेंद गोयल, अजय तिवारी, सत्येंद्र वर्मा, मनोज गोयल आदि रहे।

फर्जी कागजों पर चल रहे अस्पतालों पर एक्शन, एक और अस्पताल सील

मऊ, संवाददाता। मऊ में अवैध तरीके से अस्पताल चलने की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर के भीटी पुल के नीचे संचालित एक अस्पताल पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि अस्पताल का पंजीयन आयुर्वेद विधा से है, लेकिन यहां इलाज ऐलोपैथ विधा से हो रहा था। इसकी सूचना पर आयुष विभाग के जिम्मेदार भी मौके पर पहुंचे, जहां जांच के बाद अस्पताल को सील कर दिया। यह बीते 72 घंटे में दूसरी कार्रवाई है, इससे पहले सिटी मजिस्ट्रेट ने एक शिकायत मिलने पर भीटी स्थित एक निजी अस्पताल पर कार्रवाई की थी। स्वास्थ्य विभाग के एसीएमओ डॉ. आरएन सिंह ने बताया कि उन्हें सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा भीटी पुल के नीचे एक अस्पताल को लेकर शिकायत मिली। जिसके बाद वह अपनी टीम के साथ संचालित प्रिंस अस्पताल पहुंचे। टीम को यहां बकायदा तीन कमरों में 10 बेड का अस्पताल संचालित होता मिला। इस दौरान एक महिला मरीज भी भर्ती होना मिली। बताया कि जांच में पता चला कि यह अस्पताल का पंजीयन आयुर्वेदिक विधा से है, लेकिन यहां इलाज ऐलोपैथ विधा से हो रहा है। इतना ही नहीं अस्पताल का पंजीयन का समय सीमा भी खत्म हो चुका है।

नियमानुसार आयुर्वेद विधा से संचालित इस अस्पताल में सिर्फ आयुर्वेदिक की दवाइयां वितरित की जानी चाहिए लेकिन यहां पर बकायदे जांच और ऑपरेशन भी किया जा रहा था। उधर स्वास्थ्य विभाग की सूचना के बाद क्षेत्रीय आयुर्वेद एवं यूनानी अधिकारी डॉ. सतेंद्र साहू मौके पर पहुंचे और जांच करने के बाद अस्पताल को सील करने की कार्रवाई की।

पुराने छात्रों की मदद से ट्रिपलआईटी में स्थापित की जाएगी गूगल लैब

प्रयागराज, संवाददाता। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (ट्रिपलआईटी) में शनिवार से दो दिवसीय रजत जयंती वैश्विक पुरा छात्र मिलन समारोह शुरू हो गया। वर्षों बाद संस्थान पहुंचे छात्र अपने साथियों से मिले तो पुरानी यादें ताजा हो गईं। एक दूसरे ने अपना अनुभव साझा किया। कुछ परिवार सहित आए तो कुछ अकेले ही। हास्टल में रहने और पढ़ाई के दौरान के अनुभव बताकर ठहाके भी लगाए। इस दौरान तीन प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों सतीश कुमार, शिवम और रोहित को सम्मानित किया गया। समारोह का उद्घाटन निदेशक प्रो. मुकुल शरद सुतावाने ने किया। उन्होंने पूर्व छात्रों से युवा पीढ़ी को उनकी जीवनशैली में धैर्य और करुणा का समावेश करके संस्थान निर्माण में भागीदार बनने के लिए आह्वान किया। कहा कि संस्थान परिसर में गूगल लैब स्थापित करने में मदद करें। प्लेसमेंट रिकॉर्ड में संस्थान नंबर एक पर है। कहा कि आप लोग नौकरी लेने वालों के बजाय नौकरी देने वाले बनें और परिसर में बार–बार आते रहें। पुरा छात्र मामलों के डीन प्रोफेसर अनुपम अग्रवाल ने 7000 से अधिक स्नातकों के पुरा छात्र संघ को परियोजनाओं, औद्योगिक– शैक्षणिक सहयोग और समझौता ज्ञापनों में संस्थान का सहयोग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संस्थान के 25 वर्ष की यात्रा प्रस्तुत की। पूर्व निदेशक प्रो. सोमनाथ बिस्वास ने अपने वीडियो संदेश में बताया कि यह संस्थान देश के सर्वश्रेष्ठ कैसे है। उन्होंने संस्थान में एआई आधारित शोध करने के लिए सुझाव दिया। जनरेटिव एआई तकनीक के विकास का सुझाव दिया, जो आईटी का एक केंद्रीय हिस्सा है। पूर्व कार्यवाहक निदेशक प्रो. जीसी नंदी ने विकास और कैंपस प्लेसमेंट के संघर्ष भरे दिनों को याद किया। आईआईटी कानपुर के निदेशक व बीओजी सदस्य पद्मश्री प्रो. मनिंद्र अग्रवाल ने वीडियो संदेश में ट्रिपलआईटी के 25 वर्ष पूरे करने की बधाई दी। कहा कि किसी भी संस्थान के विकास में पूर्व छात्रों की भूमिका अहम होती है। पूर्व निदेशक और विज्ञान विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश के कुलपति प्रो पी नागभूषण ने वीडियो संदेश के माध्यम से संस्थान की उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। पूर्व छात्र अतिथि सतीश कुमार ने शुरुआती दिनों को याद किया। बताया कि कैसे वह इसरो में वैज्ञानिक के रूप में पहुंचे और आखिरकार आईईएस और अब दूरसंचार नियामक सेवाओं में हैं। उन्होंने युवा छात्रों को सरकारी नौकरियों के लिए प्रोत्साहित किया। पूर्व छात्र अतिथि शिवम ने संकायों और निदेशक को उनके शोध विकास के लिए दीर्घकालिक बीज के रूप में धन्यवाद दिया। बताया कि कैसे एआई वैश्विक पदचिह्न को विनियमित करने में मदद कर सकता है। पूर्व छात्र अतिथि रोहित श्रीवास्तव ने कहा कि वह और उनकी पत्नी दोनों ट्रिपल आईटी के पूर्व छात्र हैं और उनकी पत्नी उद्योग की सह–संस्थापक भी हैं। उन्होंने सबसे बड़े उद्योगों में से एक स्टार्टअप की स्थापना की है। मेटा एआई में शोध कर्मचारी और पूर्व छात्र आशीष पप्पू ने छात्रों को जनरेटिव एआई, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण पर काम करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने छात्रों को डेटा–संचालित प्रक्रियाओं के लिए उद्योग के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। पुरा छात्र ऋषभ अग्रवाल, अरविंद, मनु शर्मा, नागेंद्र शर्मा, मनोज सिंह, पवन कुमार केसरवानी आदि पुराने साथियों से मिलकर भावविभोर हो गए। कार्यक्रम में प्रो पवन चक्रवर्ती ने धन्यवाद ज्ञापन दिया। शाम को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया।

केबिन में बुलाकर करते हैं अश्लील हरकत, पूर्वांचल विवि की छात्रा का प्रोफेसर पर आरोप

जौनपुर, संवाददाता। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस विभाग में संविदा पर तैनात सहायक प्रोफेसर डॉ. सुधीर उपाध्याय पर प्रथम वर्ष की छात्रा ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। छात्रा ने कुलपति को पत्र लिखकर शिकायत की है। कुलपति प्रो वंदना सिंह ने टीम गठित कर आदेश दिए हैं। कमेटी की जांच के अध्यक्ष डा. नूपुर गोयल बनाई गई हैं। डॉ. नूपुर ने बताया कि आंतरिक शिकायत जांच प्रकोष्ठ के पास आया है। जांच के बाद रिपोर्ट कुलपति को दी जाएगी। इस समिति में कुल 11 सदस्य शामिल हैं। वहीं, पुलिस की आईटी टीम और सराय ख्वाजा थाने की पुलिस ने भी शनिवार को विश्वविद्यालय पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। अभी तक सहायक प्रोफेसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। छात्रा ने आरोप लगाया है कि सहायक प्रोफेसर उसे नियमित रूप से व्हाट्सएप कॉल और चौटिंग के माध्यम से परेशान करते थे। केबिन में बुलाकर अश्लील हरकतें करते थे। छात्रा ने ऑडियो भी कुलपति को सौंपा है। थाना प्रभारी राज नारायण चौरसिया ने बताया कि पुलिस की मीडिया सेल से जानकारी मिली थी। जानकारी इकट्ठा की है। वहीं, प्रोफेसर छुट्टी पर चले गए हैं।

बिजली कड़कने से बत्ती गुल, 200 स्मार्ट मीटर खराब–गुल रही आपूर्ति

गोरखपुर, संवाददाता। बिजली कड़कने से शनिवार की दोपहर सिंघड़िया क्षेत्र के करीब 200 घरों में लगे स्मार्ट मीटर खराब होने से बिजली गुल हो गई। शिकायत पर बारिश बंद होने के बाद बिजली कर्मचारी मौके पर पहुंचे। कुछ उपभोक्ताओं के मीटर बदले गए तो कुछ घरों की आपूर्ति बहाल करने के लिए बाइपास का सहारा लिया गया। बारिश के बीच दोपहर करीब 12 बजे तेज आवाज के साथ बिजली कड़की तो सिंघड़िया क्षेत्र के उपभोक्ता विंदा, सरिता यादव, उत्तम पांडेय, अखिलेश मौर्या, नंद किशोर सिंह, वंदना यादव, सुमित्रा शर्मा, चंद्रकला, खुर्शीद अली, गौरी देवी, लीलावती व सुधा देवी सहित तकरीबन 200 घरों में लगे स्मार्ट मीटर ने काम करना बंद कर दिया, जिससे सभी घरों की बिजली गुल हो गई। बत्ती गुल होते ही प्रभावित घरों के सदस्य परेशान हो उठे, उन्होंने विभाग को इसकी सूचना दी। सूचना के बाद बारिश के बंद होते ही बिजली कर्मचारी मौके पर पहुंचे। एक साथ इतने मीटरों को बदला संभव नहीं था, लिहाजा कई उपभोक्ताओं की आपूर्ति बहाल करने के लिए बाईपास का सहारा लिया गया। बता दें कि जो मीटर पूरी तरह डैमेज हो गए होंगे, उन्हें बदलना ही पड़ेगा, जबकि कुछ ऐसे भी मीटर हो सकते हैं जिनके चिप को बदल कर सही किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी स्मार्ट मीटर लगाने वाली कंपनी की होती है। जेई खोराबार शिवम चौधरी ने बताया कि खराब हुए मीटरों की संख्या अधिक होने के चलते जिन उपभोक्ताओं के मीटर बदले नहीं जा सकेंगे, उन्हें बाईपास के जरिये आपूर्ति देने की व्यवस्था की गई है।

जिला पंचायत की बैठक में दो विधायक भिड़े

महराजगंज, संवाददाता। जिला पंचायत की बैठक में दो विधायक आपस में भिड़ गए। इसके बाद माहौल कुछ देर के लिए गर्म हो गया। बाद में बैठक शुरू हुई। अधिकारियों के नहीं रहने पर भी आपत्ति जताई गई। बैठक में प्रतिनिधियों की उपस्थिति पर भी विरोध हुआ। बैठक में फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी ने जिला पंचायत में भ्रष्टाचार का आरोप मढ़ा तो हंगामा होने लगा। माहौल शांत हुआ तो बैठक में चर्चा का क्रम आगे बढ़ा। चर्चा है कि जनप्रतिनिधि की बात व बजट को लेकर दोनों आपस में असहमत थे। जिसपर मंच पर ही सबके सामने तेज आवाज में बात करने लगे। एक ने कहा जनप्रतिनिधि का जगह कोई और नहीं रह सकता तो दूसरे ने कहा कि जनप्रतिनिधि का ही रहना अनिवार्य है। मंच पर विधायकों को आपस में लड़ते देख कुछ जिला पंचायत सदस्यों ने ठहाका लगाया। जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल, विधायक पनियरा ज्ञानेंद्र सिंह, विधायक नौतनवा ऋषि त्रिपाठी, विधायक सिसवा प्रेमसागर पटेल व विधायक सदर जयमंगल कन्नौजिया मंच पर बैठे रहे। सामने जिला पंचायत के सदस्य व अधिकारी बैठे रहे। कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई फरेंदा विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि शासनादेश के अनुसार ही बैठक में जनप्रतिनिधि स्वयं रहें। बैठक में शामिल होने के लिए एएमए की ओर से जो पत्र जारी किया गया है उसका पालन किया जाए। बैठक में मौजूद प्रतिनिधि पर फरेंदा विधायक ने आपत्ति जताई। इस पर एक सत्ताधारी दल के विधायक ने बचाव करते हुए कहा कि अगली बार से यह नियम लागू किया जाए। जिला पंचायत सदस्यों ने सड़क, बिजली, पानी का मुद्दा उठाया। जिला पंचायत सदस्य सुरेश चंद्र साहनी ने कहा वृद्धा, विधवा, दिव्यांग में पात्रों को अपात्र न बनाया जाए।

प्रमुख पनियरा ने जर्जर सड़क का मुद्दा उठाया

जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में ब्लॉक प्रमुख पनियरा वेद प्रकाश शुक्ल ने अपने क्षेत्र में आने वाली जिला पंचायत की क्षतिग्रस्त सड़क का मुद्दा से उठाया। बभनौली, लक्ष्मीपुर, देउरवा मार्ग के विशेष अनुरक्षण की मांग करते हुए पत्र भी दिया। बभनौली चौराहे से विशुनपुरा निवासी राममूरत प्रसाद वर्मा के घर तक एक किमी सीसी रोड के निर्माण और शेष विशुनपुरा से लक्ष्मीपुर देउरवा तक 1.5 किमी लेपन जरूरी है।

जिला पंचायत में कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है काम

जिला पंचायत बोर्ड की बैठक में आए कांग्रेस से फरेंदा के विधायक वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि जिला पंचायत भ्रष्टाचार का अड्डा है। यहां 43 फीसदी कमीशन पर काम होता है। इसको लेकर वह विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठा चुके हैं। कमीशन पर उन्होंने कहा कि किसी भी सदस्य से पूछ लीजिए। 43 फीसदी कमीशन के बाद आपको लगता है कि सड़क पर कुछ काम नजर आएगा। यहां सिर्फ लूट है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में ई–टेंडर पड़ रहा है, लेकिन महराजगंज जिला पंचायत में कुछ चुनिंदा लोगों को ही काम मिलता है। विधायक ने मानसून आफर पर कहा कि जिला पंचायत में 47 सदस्य हैं। बोर्ड की जितना बजट है कर्मियों, अधिकारियों व पदाधिकारियों का वेतन देने के बाद जितना धन बचे उससे क्षेत्र में विकास कार्य कराने के लिए सदस्यों में बराबर–बराबर बांट देना चाहिए। यही तो मानसून आफर है, लेकिन सदस्य यहां के सीधे हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी सीधे हैं। खेती–किसानी से जुड़े हैं।

इंटरलाकिंग सड़क बनाने व फिर उसे उखाड़ने का मुद्दा उठा

जिला पंचायत की बैठक के बाद अध्यक्ष के सामने एनएच 730 एस महराजगंज ठूठीबारी मार्ग पर बरोहिया में डेढ़ करोड़ से इंटरलाकिंग सड़क बनाने व फिर उसे उखाड़ने के बाद ईंट की लूट पर सवाल उठा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि इंटरलाकिंग सड़क के लिए वह पीडब्ल्यूडी से एनओसी लिए थे। बाद में सड़क चौड़ीकरण की स्वीकृति मिली। उसके पहले इंटरलाकिंग हो चुका था। ईंट को उठाकर एक स्कूल में भेजने के सवाल पर जिला पंचायत अध्यक्ष का कहना है कि आरोप निराधार है।

बाइक सवार बदमाशों ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख को मारी गोली

प्रयागराज, संवाददाता। उतरांव थाना क्षेत्र के दुघरा गांव निवासी और सैदाबाद ब्लॉक के पूर्व ब्लाक प्रमुख राधेश्याम पटेल को बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। घटना सलेमपुर किसान मंडी फरीदपुर के पास रविवार को दोपहर में हुई। गोली ब्लॉक प्रमुख के पेट में लगी है।

घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश भागने में सफल रहे। घायलावस्था में उन्हें एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। दुघरा गांव निवासी राधेश्याम पटेल रविवार को सुबह नौ बजे घर से खाना खाकर अपने बाइक से चालक अनिल कुमार के साथ फूलपुर मंडी के लिए निकले थे। फूलपुर मंडी से वापस घर के लिए लौट रहे थे किसान मंडी फरीदपुर के पास चलती बाइक पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे से उनके ऊपर फायर कर दिया। गोली उनके पेट में लगी। फायरिंग के बाद बदमाश भाग निकले। सूचना पाकर परिवार के लोग पहुंच गए और उन्हें उपचार के लिए एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया। प्रमुख राधेश्याम से कुछ लोगों से पुरानी रंजिश चली आ रही है। गांव में भी एक व्यक्ति से जमीन को लेकर रंजिश चल रही है। उसने भी जान से मारने की धमकी दी थी। इसके खिलाफ थाने पर मुकदमा भी पंजीकृत है। इस मामले में थाना अध्यक्ष उतरांव पंकज त्रिपाठी ने बताया कि प्रमुख राधेश्याम पटेल के बयान के मुताबिक चार लोगों को आरोपी बनाया गया है। तीन लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। एक की तलाश जारी है। मामले की जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

सान्ध्य हिन्दी दैनिक देश की उपासना

स्वात्वाधिकारी में. प्रभुदयाल प्रकाशन की ओर से श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक द्वारा देश की उपासना प्रेस, उपासना भवन, धर्मसारी, प्रेमापुर, जौनपुर उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं प्रकाशित।

सम्पादक
श्रीमती किरन देवी श्रीवास्तव
मो0 - 7007415808, 9628325542, 9415034002
RNI NO - UPHIN/2022/86937
Email - deshkiupasanadailynews@gmail.com

समाचार–पत्र से संबधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र जौनपुर न्यायालय होगा।